सुरक्षित निर्णय

समक्ष उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल

रिट याचिका (एस/ बी) संख्या. 173/ 2018

डॉ. अनिता यादव ...याचिकाकर्ता।

बनाम

गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय एवं

प्रौद्योगिकी, पंतनगर, उधम सिंह नगर और अन्य।

...प्रतिउत्तरदा

ता।

श्री सी.डी. बहुगुणा, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री ए.के. वर्मा, विद्वान अधिवक्ता याचिकाकर्ता. द्वारा सहायता प्राप्त ।

श्री राजेंद्र डोभाल, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री देवांग डोभाल, विद्वान अधिवक्ता द्वारा सहायता प्राप्त प्रतिवादी संख्या के लिए 1, 2 और 4. के लिए

श्री कार्तिकेय हरि गुप्ता, प्रतिवादी संख्या 3 के लिए विद्वान अधिवक्ता ।

श्री विनय कुमार, प्रतिवादी संख्या के विद्वान वकील।

तथा

रिट याचिका (एस/ बी) संख्या. 153/ 2018

विनीत कुमार ...याचिकाकर्ता।

बनाम

जी.बी. पंत कृषि विश्वविद्यालय एवं

प्रौद्योगिकी, पंतनगर, और अन्य। ...प्रतिउत्तरदाता।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री विनय कुमार।

श्री राजेंद्र डोभाल, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री देवांग डोभाल द्वारा सहायता प्राप्त, प्रतिउत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता

फैसला सुरक्षित: 18.12.2018

फैसला सुनाया गया: 22.02.2019

संदर्भित मामलों की कालानुक्रमिक सूची:

1. एआईआर 1958 एससी 36
2. एआईआर 1974 एससी 2192
3. एआईआर 1984 एससी 636
4. (1984) 3 एससीसी 384

5. (1991) 1 एससीसी 691
6. एआईआर 1964 एससी 449
7. एआईआर 1961 एससी 177
8. सी.ए. क्रमांक 590/62 दिनांक 23.10.1963 को निर्णय हुआ
9. एआईआर 1964 एससी 1854
10. सी.ए. क्रमांक 1341/66 दिनांक 13.12.1966 को निर्णय हुआ
11. एआईआर 1968 एससी 1089
12. एआईआर 1963 एससी 1552
13. एआईआर 1971 एससी 1011
14. (1964) आईएलजे 68 एससी
15. (1971) 2 एससीआर 118
16. (2000) 3 एससीसी 588
17. (1980) आईएलजे 137 एससी
18. (2008) 3 एससीसी 310
19. (1960) आईएलजे 577 एससी
20. (1992) 2 एससीसी 683
21. (2005) 7 एससीसी 177
22. एआईआर 2008 एससी 578
23. (1988) सपोर्ट एससीसी 795
24. (2008) 11 एससीसी 314
25. (2016) 8 एससीसी 471
26. (2003) 3 एससीसी 437
27. (2010) 2 एससीसी 169
28. एआईआर 1967 एससी 1269
29. (1993) 3 एससीसी 259
30. एआईआर 1972 एससी 1680
31. (1973) 1 एससीआर 258
32. एआईआर 1956 पी एंड एच 201
33. एआईआर 1953 काल 653
34. एआईआर 1952 कैल 808
35. 2009 (5) एएलडी 273
36. (1981) 1 एससीआर 746
37. (2002) 1 एससीसी 113

कोरम: <u>माननीय रमेश रंगनाथन, सी.जे.</u>
<u>माननीय आलोक सिंह, जे.</u>

<u>रमेश रंगनाथन, सी.जे.</u>

रिट याचिका (एस/ बी) संख्या 153/2018 डॉ. विनीत कुमार द्वारा दायर की गई है जिसके द्वारा उत्तरदाताओं को कृषि महाविद्यालय, गोविंद बल्लभ पंत में विश्वविद्यालय में उनके उम्मीदवारी उम्मीदवारी रोजगार

सूचना क्रमांक ए-20/2015 दिनांक 05.06.2015 पर सहायक प्रोफेसर (जेनेटिक्स और पादप प्रजनन) के पद पर नियुक्ति के लिए विचार करने का निर्देश देने के लिए परमादेश रिट की मांग की जितना कि वह चयन/ अनुशंसा सूची में दूसरे स्थान पर था, और चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति में विज्ञापन की शर्तें.तथा नियमों का उल्लंघन पाया गया

2. रिट याचिका (एस /बी) संख्या 173/ 2018 डॉ. अनीता यादव द्वारा दायर किया गया है जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 और 3 (अतिरिक्त मुख्य सेर्मिक अधिकारी और गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय के कुलाधिपति) द्वारा पारित आदेश दिनांकित 04.04. 2018 और 14.09.2017 को अपास्त करने के लिए परमादेशों रिट की मांग की गई है। यह घोषणा करते हुए कि दिनांक 13.03.2018 के विवादित परमादेश में निहित प्रबंधन बोर्ड से संकल्प, विश्वविद्यालय के अधिनियम और संविधि' के प्रावधानों से पालन नहीं करने के लिए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर ध्यान न देने के लिए, और कुलाधिपति के विचारों को पुनः प्रस्तुत करने के लिए, याचिकाकर्ता को खंडवा खंड हटाने के लिए, इस संबंध में अनुशासनात्मक कार्यवाही/जांच शुरू किए बिना; अनुबंध/रोजगार अनुबंध के पैरा 7 के साथ-साथ अध्याय XX की धारा 4 (ई) (2) घोषित करने के लिए अनिवार्य लिखित परमादेश। 1 खंड 4 कृषि महाविद्यालय, गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर, उधम सिंह नगर में सहायक प्रोफेसर, आनुवंशिकी और पादप प्रजनन के रूप में याचिकाकर्ता के सेम में हस्तक्षेप न करना और उखंड कृषि महाविद्यालय, G.B पंत विश्वविद्यालय, पंतनगर में सहायक प्रोफेसर, आनुवंशिकी और पादप प्रजनन के रूप में सेम करने और जारी रखने की अनुमति देना।

3. रिट याचिका (एस/बी) नं. में याचिकाकर्ता। 2018 के 153 को रिट याचिका (एस/बी) संख्या में 5वें प्रतिवादी के रूप में रखा गया है। 2018 का 173।इसलिए, इन दोनों रिट याचिकाओं का अब एक सामान्य आदेश द्वारा निपटारा किया जा रहा है।इसके बाद दलों को रिट याचिका (एस/बी) संख्या में उल्लिखित किया जाएगा। 2018 का 173।याचिकाकर्ता और पाँचवें प्रतिवादी दोनों ने प्रतिवादी विश्वविद्यालय के कृषि महाविद्यालय में सहायक प्रोफेसर (आनुवंशिकी और पादप प्रजनन) के पद पर नियुक्ति के लिए अपने आवेदन प्रस्तुत किए।रोजगार सूचना सं। ए-<आईडी1>, जून, 2015 में समाचार पत्रों में प्रकाशित और विज्ञापित, गोविंद वल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर, उधम सिंह नगर (इसके बाद "प्रतिवादी-विश्वविद्यालय" के रूप में संदर्भित) ने सहायक प्रोफेसर, आनुवंशिकी और पादप प्रजनन, (कृषि महाविद्यालय) के पद सहित कई पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए, जो अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ. बी. सी.) श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों के लिए आरक्षित था। याचिकाकर्ता ने कृषि महाविद्यालय में सहायक प्रोफेसर, आनुवंशिकी और पादप प्रजनन के पद के लिए, ओ. बी. सी. श्रेणी में, 18.06.2015 पर आवेदन किया। विज्ञापन (रोजगार सूचना सं। ए 20/ 2015 ने निर्धारित किया कि जिन उम्मीदवारों ने विज्ञापन में शामिल पदों के लिए दिनांक ए-18/ 2011 दिनांक 07.01.2012 के विज्ञापन के जवाब में पहले आवेदन किया था, उन्हें आवश्यक आवेदन शुल्क का भुगतान करने यद्यपि आवश्यकता नहीं है; हालाँकि, उन्हें अपनी उम्मीदवारी पर विचार करने के लिए एक नया आवेदन जमा करना चाहिए।चूंकि याचिकाकर्ता ने पहले आवेदन किया था, विज्ञापन दिनांक 07.01.2012 के जवाब में, इस शर्त ने उसे आवश्यक आवेदन शुल्क का भुगतान नहीं करने में सक्षम बनाया।हालाँकि, उन्हें ए-20/ 2015दिनांकित रोजगार सूचना के संदर्भ में एक नया आवेदन जमा करने यद्यपि आवश्यकता थी।

4. उक्त सूचना दिनांक 05.06.2015 में संलग्न आवेदन पत्र में कुछ विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी।खंड 10 (ए) में आवेदक से यह बताने की आवश्यकता थी कि क्या उसे कभी गिरफ्तार किया गया था या उस पर मुकदमा चलाया गया था।खंड 10 (बी) उम्मीदवार से यह बताने की अपेक्षा करता है कि क्या उसे विश्वविद्यालय द्वारा दंडित किया गया था; और खंड (10) (सी) उम्मीदवार से यह बताने की अपेक्षा करता है कि क्या उसे कभी किसी सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र संगठन/अर्ध-सरकारी संगठन से बर्खास्त/छुट्टी दी गई थी।यदि उत्तर सकारात्मक था, तो उम्मीदवार को विवरण देना आवश्यक था।आवेदन पत्र के खंड 14 में आवेदक से नियोक्ता का पता, पद धारण, वेतनमान, सेवा की अवधि (से), किए गए काम का विवरण और जाने का कारण के साथ अपना रोजगार अभिलेख प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।खंड (15) में वर्तमान नियोक्ता द्वारा आवेदन को अग्रेषित करने की आवश्यकता थी।

5. आवेदन पत्र के घोषणा भाग का खंड (ए), जिस पर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर किए जाने की आवश्यकता थी, उसे यह घोषित करने की आवश्यकता थी कि प्रपत्र में प्रविष्टियां उसके ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही थीं, और यह भी कि उसने कोई तथ्य नहीं छिपाया था या अपनी पिछली सेवा और रिकॉर्ड के बारे में कोई जानकारी नहीं रोकी थी; और यदि कोई प्रविष्टि झूठी या गलत पाई गई थी, या यदि कुछ भी छिपाया गया था, तो उसे चयन के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा या यदि नियुक्त किया जाता है तो वह बिना किसी सूचना या मुआवजे के समाप्त होने के लिए उत्तरदायी होगा।घोषणा के खंड (बी) में आवेदक को यह प्रमाणित करने की आवश्यकता होती है कि उसने रोजगार सूचना को ध्यान से पढ़ा है।

6. उसके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में, याचिकाकर्ता ने खंड 10 (बी) के संबंध में, जिसमें उसे यह बताने की आवश्यकता थी कि क्या उसे कभी विश्वविद्यालय द्वारा दंडित किया गया था, "नहीं" के रूप में उत्तर दिया।कॉलम (14) i.e के संबंध में। नियोक्ता के पते, पद धारण, वेतनमान, सेवा की अवधि (कहाँ से कहाँ तक), किए गए काम का विवरण और जाने के कारण के साथ रोजगार अभिलेख, उसने लिखा "लागू नहीं"।याचिकाकर्ता ने घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, 18.06.2015 पर। 5वें प्रतिवादी ने भी 13.09.2015 पर अपना आवेदन जमा किया।

7. जुलाई 2015 के महीने में, विश्वविद्यालय की जांच समिति ने साक्षात्कार के लिए याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी की सिफारिश की, जिसके अनुसार याचिकाकर्ता साक्षात्कार के लिए चयन समिति के समक्ष उपस्थित हुआ।सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति के लिए साक्षात्कार 30.09.2015 पर आयोजित किए गए थे और याचिकाकर्ता को 85.75 अंक दिए गए थे, जबकि 5वें प्रतिवादी को 82.25 अंक दिए गए थे।याचिकाकर्ता को सीरियल नं. 1, और क्रम संख्या में 5 वां प्रतिवादी। 2, सिफारिश सूची में।

8. 5वें प्रतिवादी ने 30.11.2015 पर लोक सूचना अधिकारी, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर को एक आर. टी. आई. आवेदन प्रस्तुत किया।आर. टी. आई. प्रश्न के जवाब में, 5वें प्रतिवादी को दिनांक 1 दिनांकित पत्र द्वारा सूचित किया गया था कि याचिकाकर्ता ने बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर में सहायक प्रोफेसर (आनुवंशिकी और पादप प्रजनन) के रूप में 31.01.2015 से 05.12.2015 तक कार्य किया था; उनके इस्तीफे की स्वीकृति प्रक्रिया में थी; प्रतिवादी विश्वविद्यालय में नियुक्ति के लिए उनसे आवेदन पत्र, बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा अग्रेषित नहीं किया गया था; और 30.09.2015 पर आयोजित होने वाले साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया गया था।याचिकाकर्ता को कृषि महाविद्यालय में सहायक प्रोफेसर, आनुवंशिकी और पादप प्रजनन के पद पर, ओ. बी. सी. श्रेणी में, 07.12.2015 की कार्यवाही के अनुसार15,600-39,100+AGP रु 6000 के वेतनमान में नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ता ने अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट 08-12-2015 पर हेड, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, G.B पंत विश्वविद्यालय, पंतनगर के समक्ष प्रस्तुत की।।

9. पांचवें प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता की नियुक्ति के संबंध में कुलाधिपति को एक अभ्यावेदन अभ्यावेदन किया, जिसमें तर्क दिया गया कि उसने बिहार कृषि विश्वविद्यालय, साबौर, भागलपुर में कार्यरत होने के तथ्य को छिपा दिया था, जब उसने सहायक प्रोफेसर (आनुवंशिकी और पादप प्रजनन) के पद पर नियुक्ति के लिए अपना आवेदन पत्र जमा किया था; और उसने पिछले नियोक्ता से अपनी एन. ओ. सी. जमा नहीं की थी।याचिकाकर्ता को सहायक प्रोफेसर (आनुवंशिकी और पादप प्रजनन) के अभ्यावेदन में नियुक्त करने में विश्वविद्यालय द्वारा की गई अनियमितताओं के बारे में 5वें प्रतिवादी के पिता द्वारा प्रतिवादी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति को 05.03.2016 पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था।

10. आर. टी. आई. आवेदन दिनांक05.03.2016 के जवाब में, प्रतिवादी विश्वविद्यालय के लोक सूचना अधिकारी ने अपने पत्र दिनांक 21.03.2016 द्वारा, आवेदन पत्र, शैक्षिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र और याचिकाकर्ता के Ph.D. पाठ्यक्रम के साथ-साथ सजा आदेश के बारे में जानकारी प्रदान की। पाँचवें प्रतिवादी ने रिट याचिका (एस/बी) नं. 156/ 2016 जिसका निपटान दिनांक 27.04.2016 के आदेश द्वारा किया गया था जिसमें कहा गया था कि याचिकाकर्ता के पास कुलाधिपति से संपर्क करने का वैकल्पिक उपाय था।इस न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि यदि याचिकाकर्ता कुलाधिपति से संपर्क करता है, तो सभी प्रभावित पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात मामले पर जल्द

से जल्द निर्णय लिया जाना चाहिए।इसके बाद 5वें प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता की नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए कुलाधिपति को अपना दिनांकित अभ्यावेदन अभ्यावेदन किया।अपने अभ्यावेदन में पांचवें प्रतिवादी ने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता ने रोजगार अधिसूचना की शर्तों का उल्लंघन करते हुए बिहार कृषि विश्वविद्यालय, साबौर, भागलपुर में अपनी पिछली नौकरी को छिपा दिया था और उसे अभ्यावेदन परिवीक्षा (सीपी) की सजा दी गई थी क्योंकि जब वह विश्वविद्यालय से अपना Ph.D पाठ्यक्रम कर रही थी तो उसे अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए पाया गया था।

11. प्रतिवादी-विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलाधिपति के कार्यालय ने विश्वविद्यालय के कुलपति से 14 जून 2016 के पत्र के माध्यम से पांचवें प्रतिवादी के आवेदन में लगाए गए आरोपों के बारे में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए कहा। एडीसनल C.P.O विश्वविद्यालय की ओर से 12 जुलाई 2016 के पत्र के माध्यम से विश्वविद्यालय ने एक जवाब प्रस्तुत किया। इसके पश्चात 5वें प्रत्यर्थी ने रिट याचिका (एस/बी) नं. 112/ 2017 जिसका निपटान दिनांक 22.03.2017 के आदेश द्वारा कुलाधिपति को याचिकाकर्ता और 5वें प्रतिवादी दोनों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात तीन महीने की अवधि के भीतर कानून के अनुसार 5वें प्रतिवादी के अभ्यावेदन पर विचार करने और निर्णय लेने का निर्देश देते हुए किया गया था।

12. याचिकाकर्ता, 5वें प्रतिवादी और विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि को सुनने के बाद और विश्वविद्यालय द्वारा दायर रिपोर्ट और 5वें प्रतिवादी के अभ्यावेदन के लिए याचिकाकर्ता द्वारा दायर जवाब पर विचार करने पश्चात कुलाधिपति ने अपने दिनांकित आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता ने अपनी पिछली नौकरी के साथ-साथ उसे सजा दिए जाने के तथ्य को छिपा दिया था, और विश्वविद्यालय के प्रबंधन बोर्ड को एक विशेष बैठक बुलाने और आदेश में उल्लिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया।विश्वविद्यालय के कुलाधिपति द्वारा पारित दिनांकित 14-09-2017 आदेश में, पाँचवें प्रतिवादी द्वारा लगाए गए आरोपों का उल्लेख किया गया है, जो इस प्रकार है-

(ए) डॉ. अनीता यादव ने अपने आवेदन में उत्तर प्रदेश के मऊ का अपना स्थायी निवासी पता दिया है; इसलिए, वह राज्य में ओ. बी. सी. श्रेणी के से आरक्षण का लाभ प्राप्त करने की हकदार नहीं है।

(ख) डॉ. अनीता यादव द्वारा साक्षात्कार के समय प्रस्तुत ओ. बी. सी. प्रमाण पत्र कानूनी रूप से सही नहीं था क्योंकि यह समय की पाबंदी थी।

(ग) डॉ. अनीता यादव ने इस तथ्य को छुपाया है कि उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2012 में अनुचित साधनों के उपयोग के लिए दंडित किया गया था।

(घ) डॉ. अनीता यादव ने आवेदन पत्र में अपनी पिछली नौकरी के तथ्य को छिपा दिया है।डॉ. अनीता यादव G.B में आवेदन करने के समय बिहार कृषि विश्वविद्यालय, साबौर, भागलपुर, बिहार की कर्मचारी थीं। पंत विश्वविद्यालय।उन्होंने न तो उचित माध्यम द्वारा आवेदन किया है और न ही बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा एन. ओ. सी. दी है।

(ङ) डॉ. अनीता यादव द्वारा दावा किया गया अनुभव सही नहीं है।

13. इसके बाद प्रबंधन बोर्ड ने याचिकाकर्ता को सेवा से हटाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया, और इसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त आयुक्त को हटा दिया गया।C.P.O। 04-04-2018 दिनांकित आदेश जारी किया जिसके तहत याचिकाकर्ता को सेवा से हटा दिया गया था।

14. 5वें प्रतिवादी के अनुरोध पर, प्रतिवादी विश्वविद्यालय के लोक सूचना अधिकारी ने दिनांक 1 की कार्यवाही के माध्यम द्वारा उन उम्मीदवारों की सूची के बारे में जानकारी प्रस्तुत की, जिनकी उम्मीदवारी को रोजगार सूचना सं. 5 के विरुद्ध सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति के लिए अस्वीकार कर दिया गया था। ए-<आईडी1> इस आधार पर कि उनका आवेदन नियोक्ता के माध्यम द्वारा नहीं भेजा गया था या क्योंकि उनका ओ. बी. सी. प्रमाण पत्र मान्य नहीं था।5वें प्रतिवादी के दिनांक 09.01.2018 के आर. टी. आई. आवेदन की प्राप्ति पर, लोक सूचना अधिकारी ने दिनांक 05.02.2018 की कार्यवाही के माध्यम से, विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट और याचिकाकर्ता के बयान के बारे में जानकारी प्रदान की, जिसे 5वें प्रतिवादी के अभ्यावेदन के विरुद्ध कुलाधिपति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

15. दिनांक 1 की कार्यवाही द्वारा, विश्वविद्यालय के अतिरिक्त मुख्य कार्मिक अधिकारी ने याचिकाकर्ता को सहायक प्रोफेसर (आनुवंशिक और पादप प्रजनन) के पद पर उनकी नियुक्ति को रद्द करने के लिए प्रबंधन बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय के बारे में सूचित किया क्योंकि उन्होंने अपनी पिछली नौकरी को छिपाकर विज्ञापन की शर्तों का उल्लंघन किया था और उन्हें सजा दी गई थी। इससे आहत होकर याचिकाकर्ता ने रिट याचिका (एस/बी) नं. 173/ 2018 दायर की । इस बीच 5वें प्रतिवादी ने रिट याचिका (एस/बी) नं. 153/ 2018 याचिकाकर्ता के स्थान पर नियुक्ति की मांग करते हुए दायर की।

16. दिनांक 04.04.2018 के कार्यालय आदेश में, याचिकाकर्ता की नियुक्ति को चुनौती देने वाले 5वें प्रतिवादी का संदर्भ दिया गया है, और शिकायत की गई है कि, अपने आवेदन में, याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित तथ्यों का उल्लेख नहीं किया था और अधूरी जानकारी प्रदान की थी; और इसलिए, उसकी नियुक्ति रद्द कर दी जानी चाहिएः

> "1. डॉ. अनीता यादव ने अपने आवेदन में उत्तर प्रदेश के मऊ का अपना स्थायी निवास पता दिया था।इसलिए, वह राज्य में ओ. बी. सी. श्रेणी के से आरक्षण का लाभ प्राप्त करने की हकदार नहीं है।
>
> 2. डॉ. अनीता यादव द्वारा साक्षात्कार के समय प्रस्तुत ओ. बी. सी. प्रमाण पत्र कानूनी रूप से सही नहीं था क्योंकि यह समय की पाबंदी थी।
>
> 3. डॉ. अनीता यादव ने इस तथ्य को छुपाया है कि उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2012 में अनुचित साधनों के उपयोग के लिए दंडित किया गया था।
>
> 4. डॉ. अनीता यादव ने आवेदन पत्र में अपनी पिछली नौकरी के तथ्य को छिपा दिया है।डॉ. अनीता यादव G.B में आवेदन करने के समय बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर, बिहार की कर्मचारी थीं। पंत विश्वविद्यालय।उन्होंने न तो उचित माध्यम द्वारा आवेदन किया था और न ही उन्हें बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा एनओसी दी गई थी।
>
> 5. डॉ. अनीता यादव द्वारा दावा किया गया अनुभव सही नहीं है।

17. इसके पश्चात मुख्य कार्मिक अधिकारी ने कहा कि पांचवें प्रतिवादी ने विश्वविद्यालय के कई अधिकारियों जैसे कुलपति, प्रबंधन बोर्ड और माननीय कुलाधिपति आदि को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था और लिखित याचिकाएं (i.e) भी दायर की थीं। डब्ल्यू. पी. एस. बी. सं. 156/ 2016 और 112/ 2017); उच्च न्यायालय ने मामले को 5वें प्रत्यर्थी के प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेने के लिए कुलाधिपति को भेजा था; और कुलाधिपति ने उचित विचार के पश्चात निम्नानुसार निर्देश दिया थाः

> ''........ डॉ. अनीता यादव को दी गई सुनवाई के दौरान यह सामने आया कि बिहार में उनकी पिछली नौकरी के तथ्य का आवेदन जमा करते समय उम्मीदवार द्वारा खुलासा नहीं किया गया था।आवेदन भी उचित माध्यम द्वारा नहीं भेजा गया था और नियोक्ता द्वारा एनओसी नहीं थी।दूसरा मुद्दा परीक्षा में उसके द्वारा अनुचित साधनों के उपयोग का है।इस बिंदु का कहीं भी उल्लेख नहीं मिला है और चयन समिति इस पृष्ठभूमि से अनजान थी।भले ही

दुराचार के लिए सजा या फटकार की संभावित मुद्रा समाप्त हो गई है, लेकिन यह उम्मीदवार को नैतिक रूप से दोषमुक्त नहीं करता है।

अब यदि चयन समिति को अनुचित साधनों के मामले और रोजगार को छिपाने और एन. ओ. सी. का उपयोग न करने के बारे में पता होता, तो क्या वे अभी भी स्वच्छ और बेदाग अभिलेख के साथ दूसरे उम्मीदवार पर उन्हें प्राथमिकता देते।एक व्यक्ति जो अनुचित साधनों का उपयोग करके परीक्षा में पकड़ा जाता है, जिसे उम्मीदवार द्वारा चुनौती नहीं दी जाती है, उससे एक शिक्षक के रूप में दूसरों के लिए शायद ही एक अच्छा उदाहरण होने की उम्मीद की जा सकती है।

यह भी स्पष्ट है कि आवेदन जांच प्रक्रिया जो इन सभी तथ्यों को पूरी तरह से नजरअंदाज करती है और वास्तव में उन्हें छुपाती है और उन्हें चयन समिति से दूर रखती है, वह शुरू से ही त्रुटिपूर्ण है।

6. इन परिस्थितियों में, कार्यपालिका की एक विशेष बैठक (i.e)। प्रबंधन बोर्ड) का गठन किया जाए और उपरोक्त तथ्यों को भी उचित निर्णय के लिए उनके सामने रखा जाए, क्योंकि वे नियुक्ति प्राधिकरण हैं।

7. अभ्यावेदन का अभ्यावेदन उपरोक्त परिस्थितियों में इस निर्देश के साथ किया जाता है कि इस आदेश के जारी होने के 07 दिनों के भीतर मामले में उपरोक्त टिप्पणियों के आलोक में निर्णय लेने के लिए विश्वविद्यालय के प्रबंधन बोर्ड की एक विशेष बैठक बुलाई जाए।

18. कार्यालय आदेश दिनांकित 04.04.2018 में अग्रेतर कहा गया है कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति का मामला 16.10.2017 पर आयोजित प्रबंधन बोर्ड की 231 वीं बैठक में रखा गया था और उचित विचार के पश्चात इसे निम्नानुसार हल किया गया थाः

"श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के 14 सितंबर 2017 के 2273 (1)/जी. एस./एड./डी. दिनांकित आदेश की निरंतरता में, माननीय प्रबंधन बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि इस विषय पर कोई भी अग्रेतर की कार्रवाई करने से पहले, श्री राज्यपाल/कुलाधिपति सं. 2273 (1)/जी. एस./एडन./डी-<आई. डी. 1> दिनांक 14 सितंबर 2017, नियम/क़ानून/सरकारी आदेशों में क्या कार्रवाई प्रदान की गई है, और इस संबंध में एक प्रस्ताव फिर से माननीय प्रबंधन बोर्ड के समक्ष अनिवार्य रूप से रखा जा सकता है ताकि इस विषय पर माननीय प्रबंधन बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जा सके।

माननीय प्रबंधन बोर्ड ने इस तथ्य का भी संज्ञान लिया कि डॉ. अनीता यादव, जिन्हें विश्वविद्यालय के आनुवंशिकी और पादप प्रजनन विभाग में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किया गया था, विश्वविद्यालय की पूर्व छात्रा रही हैं।उन्होंने इस विश्वविद्यालय से स्नातक, स्नातकोत्तर और Ph.D पाठ्यक्रम में अध्ययन किया है।वर्ष 2012 में विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई के दौरान, उन्हें अनुचित साधनों के उपयोग का दोषी पाया गया था।डॉ. अनीता यादव विश्वविद्यालय के कृषि महाविद्यालय की छात्रा बनी रहीं, उस स्थिति में डॉ. अनीता यादव के आवेदन पत्र की जांच करने वाली कृषि महाविद्यालय की जांच समिति को वर्ष 2012 में डॉ. अनीता यादव द्वारा अनुचित साधनों के उपयोग के बारे में पता होना चाहिए था।माननीय प्रबंधन बोर्ड ने वर्ष 2012 में डॉ. अनीता यादव द्वारा अनुचित साधनों के उपयोग के बारे में और डॉ. अनीता यादव द्वारा अनुचित साधनों के उपयोग के बारे में कोई जानकारी नहीं होने के बारे में और इसे अपनी अगली बैठक में प्रबंधन बोर्ड के समक्ष रखने के लिए जांच समिति से स्पष्टीकरण प्राप्त करने का भी निर्देश दिया था।

19. दिनांक 04.04.2018 के उक्त आदेश में यह भी दर्ज किया गया है कि जांच समिति के सदस्यों से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के पश्चात याचिकाकर्ता की नियुक्ति से संबंधित प्रस्ताव को प्रबंधन बोर्ड की दिनांक 13.03.2018 की बैठक में रखा

गया था और मामले पर विचार करने के पश्चात प्रबंधन बोर्ड ने निम्नलिखित तथ्यों को दर्ज किया था जो उसके संज्ञान में आएः

"1. डॉ. अनीता यादव द्वारा विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर, आनुवंशिकी और पादप प्रजनन के पद पर नियुक्ति के आदेश दिनांकित 18.06.2015 आवेदन पत्र में, उन्होंने बिंदु संख्या पर तथ्यों को छुपाया। 10 (ख)- क्या आपको कभी इस विश्वविद्यालय द्वारा दंडित किया गया है, इस संबंध में उन्होंने 'नहीं' लिखा है जबकि डॉ. अनीता यादव पर अतीत में कुलसचिव सं. आर. ई. जी./एस. ओ./डी. सी./<आईडी2> दिनांकित <आईडी1>।इस तरह डॉ. अनीता यादव ने बिंदु संख्या पर तथ्य को छिपा दिया। सहायक प्रोफेसर, आनुवंशिकी और पादप प्रजनन के पद पर नियुक्ति के लिए दिनांकित 18.06.2015 आवेदन पत्र का 10 जो तथ्यों को छिपाता है।

2. विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर और पादप प्रजनन के पद पर नियुक्ति के लिए डॉ. अनीता यादव द्वारा दिनांकित 18.06.2015 आवेदन पत्र में, उन्होंने बिंदु संख्या पर तथ्यों को छुपाया। 14-रोजगार अभिलेख, उन्होंने इस संबंध में लिखा 'लागू नहीं' जबकि डॉ. अनीता यादव पहले बिहार कृषि विश्वविद्यालय, साबौर, भागलपुर में काम कर रही थीं और विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर, आनुवंशिकी और पादप प्रजनन के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र में उन्होंने अपना आवेदन भेजने के स्थान का उल्लेख किया।इस तरह डॉ. अनीता यादव ने बिंदु संख्या पर तथ्य को छिपा दिया। सहायक प्रोफेसर, आनुवंशिकी और पादप प्रजनन के पद पर नियुक्ति के लिए दिनांकित 18-06-2015 आवेदन पत्र का 14, जो तथ्यों को छिपाता है।

3. प्रकाशित विज्ञापन में नं. ए-20/ 2015 सहायक प्रोफेसर आनुवंशिकी और पादप प्रजनन के पद पर विश्वविद्यालय में नियुक्ति के लिए, यह स्पष्ट रूप द्वारा उल्लेख किया गया है कि 'द्वारावा में उम्मीदवारों को उचित माध्यम द्वारा अपना आवेदन भेजना चाहिए' जबकि डॉ. अनीता यादव ने अपने पिछले नियोक्ता बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर के माध्यम द्वारा सहायक प्रोफेसर, आनुवंशिकी और पादप प्रजनन के पद के लिए अपना आवेदन पत्र दिनांक 18.06.2015 नहीं भेजा है। इस तरह डॉ. अनीता यादव ने सहायक प्रोफेसर, आनुवंशिकी और पादप प्रजनन के पद पर विश्वविद्यालय में नियुक्ति के लिए प्रकाशित विज्ञापन संख्या ए-20/ 2015 के विरुद्ध अपने आवेदन पत्र दिनांक 18-06-2015 में निहित उपरोक्त शर्त का पालन नहीं किया है। ।

4. सहायक प्रोफेसर, आनुवंशिकी और पादप प्रजनन का एक पद क्रमिक संख्या 10 में ओ. बी. सी. के लिए आरक्षित है, विश्वविद्यालय का प्रकाशित विज्ञापन सं। ए-20/ 2015 , जिसके लिए डॉ. अनीता यादव ने अपने आवेदन पत्र दिनांक 18.06.2015 द्वारा आवेदन किया था।उपरोक्त पद के लिए गठित जांच समिति ने अपनी सिफारिश में उल्लेख किया है-"हाल ही में कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता है"।

अन्य पिछड़े वर्गों का प्रमाण पत्र, सं। 8602 0202041401865, दिनांक 02-06-2014, तहसीलदार, किच्छा, U.S नगर द्वारा जारी किया गया, मात्र एक वर्ष के लिए मान्यता प्राप्त है।इस तरह उक्त कास्ट प्रमाणपत्र को 01-06-2015 तक पहचाना जाता है।जबकि डॉ. अनीता यादव ने प्रकाशित विज्ञापन संख्या के विरुद्ध अपना आवेदन दिनांक 18 06-2015 पर भेजा है। ए-<आईडी1> सहायक प्रोफेसर, आनुवंशिकी और पादप प्रजनन के पद पर नियुक्ति के लिए।इस तरह उक्त प्रमाणपत्र समय के साथ समाप्त हो जाता है।

5. डॉ. अनीता यादव ने सहायक प्रोफेसर, आनुवंशिकी और पादप प्रजनन के पद पर विश्वविद्यालय में नियुक्ति के लिए अपने आवेदन पत्र दिनांक 18-06-2015 में निम्नलिखित घोषणा की हैः

"(ए)।मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि प्रपत्र में प्रविष्टियाँ मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं और यह भी कि मैंने किसी भी तथ्य को नहीं छिपाया है या अपनी पिछली सेवा और अभिलेख के बारे में कोई जानकारी नहीं रखी है और यदि कोई प्रविष्टि झूठी या गलत पाई जाती है या यदि कुछ भी छिपाया गया पाया जाता

है तो मुझे चयन के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा या यदि नियुक्त किया जाता है तो बिना किसी सूचना या मुआवजे के समाप्त करने के लिए उत्तरदायी होगा।

20. दिनांक 04.04.2018 के उक्त आदेश में दर्ज किया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर अनुबंध/बांड के पैरा 7 में एक प्रतिबंध है कि कर्मचारी की खंडवा को किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है, यदि कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत योग्यता, अनुभव, अधिवास जाति या अन्य आरक्षित श्रेणी का कोई प्रमाण पत्र नकली और मनगढ़ंत पाया जाता है; याचिकाकर्ता ने सहायक प्रोफेसर, आनुवंशिकी और पादप प्रजनन के पद पर विश्वविद्यालय में नियुक्ति के लिए दिनांकित 18.06.2015 के आवेदन पत्र में उपरोक्त तरीके खंड तथ्यों को छुपाया था; याचिकाकर्ता का कार्य, कृषि विश्वविद्यालय, साबौर में अपनी नियुक्ति को छिपाते हुए, इस तथ्य को छिपाते हुए कि उखंड दो खंडमेस्टर (i.e) के लिए अस्थायी बर्खास्तगी की सजा दी गई थी। II खंडमेस्टर 2011-12 और I खंडमेस्टर 2012-13), विश्वविद्यालय में अपने प्रवास के दौरान संचालन परिवीक्षा पर रहने के लिए, और हाल ही में जाति प्रमाण पत्र जमा करने में उनकी विफलता, "किसी भी अधिनियम के कमीशन की श्रेणी में आती है, जिसमें बोर्ड की मत में, नैतिक अधमता शामिल है", जो क़ानून के अध्याय 25 की धारा 4 (ई) (2) के से किसी भी कर्मचारी की खंडवा को समाप्त करने के लिए पर्याप्त आधार है; और इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, प्रबंधन बोर्ड ने आदेश दिया था कि याचिकाकर्ता को तुरंत खंडवा खंड हटा दिया जाए।उक्त आदेश का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः

> "डॉ. अनीता यादव का कृषि विश्वविद्यालय, साबौर में अपनी नियुक्ति को छिपाने का कार्य (2) दो सेमेस्टर (i.e, द्वितीय सेमेस्टर 2011-12 और प्रथम सेमेस्टर 2012-13) के लिए अस्थायी बर्खास्तगी खंड सजा प्राप्त करने और विश्वविद्यालय में रहने के दौरान परिवीक्षा का संचालन करने और साक्षात्कार खंड तिथि को हाल ही में जाति प्रमाण पत्र जमा नहीं करने के तथ्य को छिपाना," किसी भी अधिनियम के आयोग खंड श्रेणी में आता है जिसमें बोर्ड खंड मत में नैतिक अधमता शामिल है, जो क़ानून के अध्याय 25 खंड धारा 4 (ई) (2) के से किसी भी कर्मचारी खंड सेवा को समाप्त करने के लिए पर्याप्त आधार है..
>
> "तदनुसार, माननीय कुलाधिपति/राज्यपाल उत्तराखंड द्वारा पारित 14 09-2017 दिनांकित उपरोक्त निर्दिष्ट आदेश के संदर्भ में, और 13 03-2018 दिनांकित अपनी 233 वीं बैठक में माननीय प्रबंधन बोर्ड द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुपालन में, जो विश्वविद्यालय अधिनियम के अध्याय 25 खंड धारा 4 (डी) (1) के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार है।डॉ. अनीता यादव सहायक प्रोफेसर, आनुवंशिकी और पादप प्रजनन (श्रेणी ओ. बी. सी.) को तुरंत विश्वविद्यालय की सेवा से हटा दिया जाता है।

21. श्री C.D द्वारा विस्तृत मौखिक और लिखित प्रस्तुतियाँ दी गईं। बहुगुणा, याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता।प्रतिवादी-विश्वविद्यालय की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजेन्द्र डोभाल और पांचवें प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री विनय कुमार द्वारा विस्तृत मौखिक प्रस्तुतियाँ की गईं।विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता और दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विभिन्न शीर्षों के से किए विद्वान प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों की जांच करना सुविधाजनक है।

I. **<u>क्या अनुशासनात्मक जांच किए बिना याचिकाकर्ता की सेवाओं को समाप्त किया जा सकता था?</u>**

22. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित श्री C.D बहुगुणा विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रस्तुत किया कि, 04-04-2018 दिनांकित आदेश द्वारा, अतिरिक्त अधिवक्ता C.P.O। विश्वविद्यालय ने याचिकाकर्ता को खंडवा खंड हटा दिया था; U.P की धारा 7 (b)। कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 (जिखंड इसके बाद "1958 अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) में कहा गया है कि विश्वविद्यालय का प्रबंधन बोर्ड विश्वविद्यालय के विद्या सम्बन्धी और प्रशासनिक कर्मचारियों की नियुक्ति का प्राधिकरण है; 1958 के अधिनियम की धारा 12 (8) के से, प्रबंधन बोर्ड की शक्तियां कुलपति को नियुक्ति और बर्खास्तगी (हटाने) के आदेशों को प्रभावी बनाने के अपास्त सौंप दी गई हैं; इसअपास्त, विश्वविद्यालय अधिनियम के खंड 4 (डी) (1) के से, कुलपति को विश्वविद्यालय के एक कर्मचारी के विरुद्ध नियुक्ति प्राधिकरण (प्रबंधन बोर्ड) की ओर खंड अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने का अधिकार दिया गया है, जहां ऐखंड कर्मचारी को हटाया जाना है।

23. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि, विश्वविद्यालय के क़ानून के अध्याय 25 के खंड 4 (डी) (1) के से पारित दिनांक04.04.2018 के विवादित आदेश में, हटाने के आदेश को मजबूत करने के अधिनियम के खंड 4 (ई) (2) का संदर्भ दिया गया है; याचिकाकर्ता को दिनांक 07.12.2015 के आदेश द्वारा सहायक प्रोफेसर (आनुवंशिकी और पादप प्रजनन) के पद पर नियुक्त किया गया था; वह 08.12.2015 पर पद पर शामिल हुई; उसने 08.12.2017 पर बिना किसी आपत्ति के 2 साल की परिवीक्षा की अवधि संतोषजनक रूप खंड पूरी की; हालाँकि पुष्टि का एक औपचारिक आदेश जारी नहीं किया गया था, विश्वविद्यालय ने अपने स्वयं के आचरण और इच्छा खंड याचिकाकर्ता को एक पुष्ट कर्मचारी के रूप में माना, और उसका सहारा लिया। याचिकाकर्ता की ओर से अवलम्ब को सर्वोच्च न्यायालय के कई फैसलों पर यह तर्क देने के लिए रखा गया है कि एक स्थायी कर्मचारी को विभागीय जांच किए बिना सेवा से हटाने की सजा नहीं दी जा सकती थी।

24. यह जाँचने से पहले कि क्या वे निर्णय, जिन पर अवलम्ब रखी गई है, वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू होते हैं, याचिकाकर्ता की ओर से दिए गए निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून ध्यान दें देना आवश्यक है।जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है, यदि सेवा की समाप्ति किसी अनुबंध या सेवा नियमों से प्राप्त अधिकार पर आधारित है, तो प्रथमदृष्टया समाप्ति कोई दंड नहीं है और इसके कोई बुरे परिणाम नहीं हैं, और इसलिए अनुच्छेद 311 आकर्षित नहीं होता है।भले ही सरकार को अनुबंध द्वारा या नियमों के से, सजा देने के लिए निर्धारित प्रक्रिया द्वारा गुजरे बिना नौकरी समाप्त करने का अधिकार है, फिर भी सरकार नौकर को दंडित करने का विकल्प चुन सकती है, और यदि द्वारावा की समाप्ति दुराचार, लापरवाही, अक्षमता या अन्य अयोग्यता पर आधारित होने की मांग की जाती है, तो यह एक सजा है और अनुच्छेद 311 की आवश्यकताओं का पालन किया जाना चाहिए।**(परशोतम लाल ढींगरा 1; शमशेर सिंह और Anr.[2]; अनूप जायसवाल 3; इंद्र पाल गुप्ता 4)**। जब भी सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान होता है कि किसी अस्थायी कर्मचारी का कार्य और आचरण संतोषजनक नहीं है, या कि सेवा में उसका बने रहना जनहित में नहीं है, या उसकी अनुपयुक्तता, दुराचार या अक्षमता के कारण, वह या तो सेवा के नियमों और शर्तों या प्रासंगिक नियमों के अनुसार उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है, या वह अस्थायी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्णय ले सकता है।यदि यह दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्णय लेता है तो यह संविधान के अनुच्छेद 311 के प्रावधानों के अनुसार आरोप तय करके और Govt.servant को एक अवसर देकर एक औपचारिक जांच कर सकता है।(**कौशल किशोर शुक्ला 5)**।

25. जिस रूप में समाप्ति का आदेश व्यक्त किया जाता है वह निर्णायक नहीं होता है।यह उस मामले का सार है जो सेवाओं की समाप्ति की प्रकृति को निर्धारित करता है, और आदेश से पहले मौजूद भौतिक तथ्यों के संदर्भ से निर्धारित किया जाना चाहिए।**(जगदीश मित्तर6**)। एक अस्थायी Govt.servant को इस पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, और इस तरह के Govt.servant की समाप्ति से उसे कोई बुरा परिणाम नहीं मिलता है। केवल 'समाप्ति' या 'निर्वहन' जैसी अभिव्यक्तियों का उपयोग निर्णायक नहीं है और इस तरह की अभिव्यक्तियों के उपयोग के बावजूद, न्यायालय आदेश की वास्तविक प्रकृति का निर्धारण कर सकता है, यह पता लगाने के लिए कि क्या Govt.servant के विरुद्ध की गई कार्रवाई दंडात्मक प्रकृति की है, दो परीक्षणों को लागू करते हुए अर्थात्:(1) क्या अस्थायी Govt.servant को पद या पद का अधिकार था, या (2) क्या उसे बुरे परिणामों के साथ देखा गया है; और यदि किसी भी परीक्षण का समाधान हो जाता है, तो यह माना जाना चाहिए कि अस्थायी Govt.servant को समाप्त करने का आदेश दंड के रूप में है।बुरे परिणामों में सेवा के नियमों और शर्तों के अनुसार अस्थायी Govt.servant की सेवाओं की समाप्ति शामिल नहीं है।(**राम नारायण दास 7 '; परशोतम लाल ढींगरा 1; R.C। लेसी8 ; चंपकलाल चिमनलाल शाह 9 ; जगदीश मित्तर6 ; A.G. बेंजामिन 1 0; शमशेर सिंह और Anr.[2]; श्री सुख राज बहादुर 1 1; कौशल किशोर शुक्ला 5 ; इंद्र पाल गुप्ता 4)**।एक अस्थायी सेवक की सेवाओं को समाप्त करने में प्राधिकरण के दिमाग में काम करने वाला उद्देश्य, समाप्ति के चरित्र को नहीं बदलता है, और उक्त चरित्र को निर्धारित करने में सामग्री नहीं है।**(परशोतम लाल ढींगरा 1; जगदीश मित्तर6)।**

26. एक परिवीक्षाधीन, जिसकी सेवा की शर्तों में कहा गया है कि इसे बिना किसी सूचना के और बिना कोई कारण बताए समाप्त किया जा सकता है, वह अनुच्छेद 311 (2) के संरक्षण का दावा नहीं कर सकता है।**(रणेंद्र चंद्र बनर्जी 1 2; समशेर सिंह 2)**।जहां एक विभागीय जांच पर विचार किया जाता है, और यदि वास्तव में एक जांच के साथ आगे नहीं बढ़ाया

जाता है, तो अनुच्छेद 311 तब तक आकर्षित नहीं होता है जब तक कि यह दिखाया नहीं जा सकता है कि आदेश, हालांकि रूप में असाधारण है, कदाचार पर आधारित एक रिपोर्ट के बाद बनाया गया है।(**शिव भिक्षुक 1 3; समशेर सिंह 2)**।प्राधिकरण, कुछ मामलों में, यह विचार रख सकता है कि परिवीक्षाधीन के आचरण के परिणामस्वरूप जांच पर बर्खास्तगी या निष्कासन हो सकता है।लेकिन उन मामलों में प्राधिकरण एक जांच आयोजित नहीं कर सकता है, और केवल परिवीक्षा की समाप्ति के समय एक कलंक के बिना जीवन के अन्य क्षेत्रों में अच्छा करने का मौका देने की दृष्टि से परिवीक्षाधीन को छुट्टी दे सकता है।यदि, दूसरी ओर, परिवीक्षाधीन को कदाचार या अक्षमता या भ्रष्टाचार के आरोपों में जांच का सामना करना पड़ता है, और यदि उसकी सेवाओं को अनुच्छेद 311 (2) के प्रावधानों का पालन किए बिना समाप्त कर दिया जाता है, तो वह सुरक्षा का दावा कर सकता है।**(शमशेर सिंह 2)**। निर्णायक बात यह है कि क्या आदेश वास्तव में सजा के रूप में है। (**राम नारायण दास 7; समशेर सिंह 2; मदन गोपाल 1 4)**। यदि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से संकेत मिलता है कि आदेश का सार यह है कि समाप्ति दंड के रूप में है तो अनुच्छेद 311 आकर्षित होगा। **(K.H. फडनीस 1 5; समशेर सिंह 2**)।यदि दंड का आदेश पारित किया जाता है, और दंडात्मक प्रकृति का होता है, तो अधिकारियों का कर्तव्य है कि वे नियमित विभागीय जांच करें, और वे कर्मचारी की सेवाओं को मनमाने ढंग से समाप्त नहीं कर सकते **(नर सिंह पाल 16)।**

27. यह ध्यान दें योग्य है कि याचिकाकर्ता को प्रतिवादी विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर (आनुवंशिकी और पादप प्रजनन) के रूप में नियुक्त किया गया था, और वह राज्य के से एक नागरिक पद पर नहीं था।एक सरकारी कर्मचारी (चाहे वह एक अस्थायी कर्मचारी हो या एक परिवीक्षाधीन), जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 के से सुरक्षा का हकदार है, के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों का वर्तमान मामले के तथ्यों पर कोई अनुप्रयोग नहीं है।

28. यहां तक कि सांविधिक निगमों और सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के मामले में भी, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि न्यायालय बर्खास्तगी के वैधानिक आदेश से जुड़ी अन्य कार्यवाही या दस्तावेजों से पता लगाएगा कि बर्खास्तगी का सही आधार क्या है।यदि, इस प्रकार जांच की जाती है, तो आदेश के कारण या परिणाम में दंडात्मक स्वाद होता है, तो यह बर्खास्तगी है।यदि यह इस परीक्षण से कम हो जाता है, तो इसे सजा नहीं कहा जा सकता है।(**गुजरात स्टील ट्यूब Ltd.17)**।इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रत्यर्थी-विश्वविद्यालय के स्थायी कर्मचारी के मामले में, विश्वविद्यालय अधिनियम सजा देने के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित करता है, जिसमें अनुशासनात्मक जांच करना शामिल है, और यदि याचिकाकर्ता ऐसा ही है, तो अलग-अलग परिणाम हो सकते हैं।

29. अगला प्रश्न, जो जांच की आवश्यकता बनाता है, यह है कि क्या याचिकाकर्ता अपने दावे में उचित है कि उसकी पुष्टि की गई है, जिसके परिणामस्वरूप उसने 07.12.2017 पर दो साल की सेवा पूरी की है।यह विवाद में नहीं है कि याचिकाकर्ता को सफलतापूर्वक अपनी परिवीक्षा पूरी करने की घोषणा करने वाला कोई विशिष्ट आदेश प्रतिवादी-विश्वविद्यालय द्वारा पारित नहीं किया गया था। श्री C.D का प्रस्तुतीकरणकरण। बहुगुणा, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, कि याचिकाकर्ता एक पुष्ट कर्मचारी है, मात्र एक स्थायी कर्मचारी पर लागू कुछ प्रावधानों के लिए दंड के विवादित आदेश में, संदर्भ से समर्थन प्राप्त करता है; और, इसे ध्यान में रखते हुए, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रस्तुत करेंगे कि यह माना जाना चाहिए कि याचिकाकर्ता की परिवीक्षा सफलतापूर्वक पूरी हो गई थी, और वह प्रतिवादी-विश्वविद्यालय की एक स्थायी कर्मचारी है।

30. इस संदर्भ में, लागू वैधानिक प्रावधानों को संदर्भित करना प्रासंगिक है।1958 का अधिनियम कृषि के विकास और उत्तर प्रदेश के ग्रामीण लोगों के लाभ के लिए कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना और उन्हें शामिल करने के लिए एक अधिनियम है।उक्त अधिनियम की खंड 2 (ए) "अकादमिक परिषद" को विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् के रूप में परिभाषित करती है।खंड 2 (सी) "बोर्ड" को विश्वविद्यालय के प्रबंधन बोर्ड के रूप में परिभाषित करती है।खंड 2 (च) "निर्धारित" को अधिनियम द्वारा निर्धारित अर्थ के रूप में परिभाषित करती है।विश्वविद्यालय के अधिकारियों को अधिनियम के से कुलाधिपति, कुलाधिपति, कुलसचिव और विश्वविद्यालय की सेवा में ऐसे अन्य व्यक्तियों को शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया है जिन्हें क़ानून द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किया जा सकता है।विश्वविद्यालय के

प्राधिकरणों में प्रबंधन बोर्ड और विद्या परिषद् शामिल हैं।1958 के अधिनियम की खंड 9 (1) में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश का राज्यपाल विश्वविद्यालय का कुलाधिपति (कुलाधिपति) होगा।धारा 9 (2) में कहा गया है कि कुलाधिपति के पास ऐसी अन्य शक्तियां होंगी जो उखंड अधिनियम या क़ानूनों द्वारा प्रदान की जा सकती हैं।धारा 10 प्रबंधन बोर्ड के गठन, शक्तियों और कर्तव्यों खंड संबंधित है।धारा 10 (7) (बी) में कहा गया है कि बोर्ड की शक्तियों और कर्तव्यों में विश्वविद्यालय के विद्या सम्बन्धी और प्रशासनिक कर्मचारियों के सदस्यों की नियुक्ति निर्धारित तरीके खंड शामिल है।धारा 12 कुलपति (कुलपति) की शक्तियों और कर्तव्यों खंड संबंधित है।खंड 12 (8) में प्रावधान है कि कुलपति विश्वविद्यालय के अधिकारियों, पेशेवर कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, निलंबन, बर्खास्तगी के संबंध में बोर्ड के आदेशों को प्रभावी बनाएगा।1958 के अधिनियम की धारा 26 वेतनभोगी अधिकारियों और शिक्षकों की नियुक्ति खंड संबंधित है।खंड 26 (1) में कहा गया है कि अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के सदस्यों की नियुक्ति कुलपति की सिफारिश पर बोर्ड द्वारा की जाएगी। धारा 26 (2) में कहा गया है कि, क़ानूनों द्वारा प्रदान किए गए मामलों को छोड़कर, विश्वविद्यालय के प्रत्येक वेतनभोगी अधिकारी और शिक्षक को एक लिखित अनुबंध के से नियुक्त किया जाएगा, अनुबंध कुलपति के पास दर्ज किया जाएगा, इसकी एक प्रति संबंधित अधिकारी या शिक्षक को प्रस्तुत की जाएगी, और अनुबंध खंडवा की शर्तों के संबंध में, वर्तमान में लागू अधिनियम और क़ानून के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं होगा।

31. धारा 26 (2) के संदर्भ में, याचिकाकर्ता और प्रतिवादी विश्वविद्यालय के बीच 07.12.2015 पर एक समझौता किया गया था।उक्त समझौते के खंड 3 में याचिकाकर्ता को परिवीक्षा पर कम से कम दो साल की अवधि के लिए विश्वविद्यालय की सेवा करने की आवश्यकता थी, जिसे दो साल की परिवीक्षा की अवधि के दौरान उसके प्रदर्शन के आधार पर बढ़ाया जा सकता था।इसने यह भी प्रावधान किया कि परिवीक्षा अवधि के दौरान, विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी समय एक महीने का नोटिस या उसके बदले में एक महीने का वेतन देकर सेवाओं को समाप्त किया जा सकता है।खंड 4 में निर्धारित किया गया है कि दो साल की परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के पश्चात यदि विस्तारित नहीं किया जाता है, तो कर्मचारी अस्थायी रूप से उक्त पद पर बने रहने का पात्र होगा, जब तक कि सेवा की समाप्ति के आदेश, जो नियमित पद के विरुद्ध होंगे, कुलपति के विवेकाधिकार पर जारी नहीं किए जाते हैं।

32. 1958 के अधिनियम की धारा 29 उस तरीके खंड संबंधित है जिसमें क़ानून बनाए जाते हैं।जबकि खंड 29 (1) में प्रावधान है कि पहला अधिनियम सरकार द्वारा बनाया जाएगा और राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा, खंड 29 (2) बोर्ड को नए या अतिरिक्त क़ानून बनाने में सक्षम बनाती है।विश्वविद्यालय अधिनियम का अध्याय XXV संख्या, योग्यता, परिलब्धि और सेवा की अन्य शर्तों से संबंधित है।इसके तहत खंड 4 सेवा, नियुक्ति, निलंबन, निष्कासन और नियंत्रण की शर्तों से संबंधित है।खंड 4 (ए) में कहा गया है कि प्रतिनियुक्ति पर सरकारी कर्मचारियों के मामले को छोड़कर, विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारियों को अधिनियम की खंड 26 (2) के से प्रावधानों के अनुसार, निर्धारित प्रपत्र में एक लिखित अनुबंध करने की आवश्यकता होगी।खंड 4 (सी) "परिवीक्षा" से संबंधित है, और खंड 4 (सी) (आई) में प्रावधान है कि विश्वविद्यालय का प्रत्येक कर्मचारी, स्थायी पद के विरुद्ध अपनी पहली नियुक्ति पर, परिवीक्षा पर होगा।खंड 4 (ग) (ii) में कहा गया है कि परिवीक्षा की अवधि आम तौर पर दो साल होगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी ने इसे दो साल से कम नहीं निर्धारित किया है और ऐसे मामलों में, इसे समय-समय पर बढ़ाया जा सकता है, लेकिन किसी भी मामले में दो साल की अवधि से अधिक नहीं होगी। खंड 4 (ग) (iii) में कहा गया है कि परिवीक्षा अवधि के अंत में कर्मचारी की पुष्टि की जा सकती है बशर्ते कि उसका काम और आचरण संतोषजनक पाया जाए और यदि उसकी पुष्टि नहीं की जाती है, तो उसकी सेवाओं को परिवीक्षा अवधि के अंत में समाप्त कर दिया गया माना जाएगा।खंड 4 (घ) में यह निर्धारित किया गया है कि अधिनियम या क़ानूनों में अन्यथा प्रावधान किए जाने के अलावा, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की वृद्धि को रोकने के अधिकार सहित कार्यालय में नियुक्ति और हटाने या किसी अन्य प्रकार की सजा, नियुक्ति प्राधिकरण के पास होगी।

33. कुलपति को कुछ शक्तियां प्रदान की गई हैं, जिनमें (क) विश्वविद्यालय के किसी भी कर्मचारी की ओर से अनियमितताओं या कदाचार के आरोपों से जुड़े तथ्यों का पता लगाने और डेटा एकत्र करने के लिए ऐसी पूछताछ करना जो वह आवश्यक समझे, (ख) विश्वविद्यालय के किसी भी कर्मचारी से स्पष्टीकरण की मांग करना, (ग) किसी भी कर्मचारी के

विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करना और उसका संचालन करना, और (घ) मामूली सजा देना जैसे कि निंदा प्रविष्टि का पुरस्कार या तीन साल से अधिक की अवधि के लिए वार्षिक वेतन वृद्धि को रोकना शामिल है।खंड 4 (ई) में कहा गया है कि पुष्टि के पश्चात विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी की सेवाओं को मात्र उसके तहत उल्लिखित आधारों पर ही समाप्त किया जा सकता है।खंड 4 (ई) (1) कदाचार से संबंधित है, जिसमें उपयुक्त प्राधिकारी के आदेश की अवज्ञा भी शामिल है।खंड 4 (ई) (2) किसी ऐसे कार्य के करने से संबंधित है जिसमें बोर्ड की मत में नैतिक अधमता शामिल है।उपखंड (ए) के तहत यह निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक कर्मचारी, जिसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का इरादा है, को लिखित अभ्यावेदन में अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जाएगा और यदि अनुशासनात्मक कार्रवाई से निपटने वाला प्राधिकरण इसे आवश्यक समझता है।

व्यक्ति।

34. मान लीजिए कि याचिकाकर्ता की सेवाओं के संबंध में अधिनियम के खंड 4 (सी) (iii) के संदर्भ में पुष्टि का कोई आदेश पारित नहीं किया गया था।सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी प्रारंभिक नियुक्ति के समय याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी-विश्वविद्यालय के बीच किए गए समझौते के खंड 4 के संदर्भ में भी, यदि दो साल की परिवीक्षा की अवधि समाप्त होने के पश्चात याचिकाकर्ता की सेवाओं की न तो पुष्टि की जाती है और न ही उन्हें बढ़ाया जाता है, तो उन्हें अस्थायी रूप से अपने पद पर बनाए रखा जाएगा। नतीजतन याचिकाकर्ता या तो परिवीक्षा पर या एक अस्थायी कर्मचारी के रूप में जारी रहा, (जब उसने परिवीक्षाधीन के रूप में दो साल पश्चात सेवा पूरी पश्चात) क्योंकि अधिनियम के खंड 4 (सी) (iii) के संदर्भ में उसपश्चात सेवाओं पश्चात पुष्टि करने वाला कोई आदेश पारित नहीं किया गया था।केवल यह तथ्य कि दिनांक 04.04.2018 का विवादित आदेश अधिनियम के खंड 4 (e) (2) को संदर्भित करता है, इसका मतलब यह नहीं है कि याचिकाकर्ता एक स्थायी कर्मचारी है, या यह कि उसकी परिवीक्षा दो साल की सेवा के पूरा होने पर घोषित की गई है, क्योंकि न तो विश्वविद्यालय अधिनियम और न ही दिनांकित 07.12.2015 समझौता याचिकाकर्ता की सेवाओं की मानित पुष्टि के लिए प्रदान करता है।इस संदर्भ में यह भी ध्यान दें प्रासंगिक है कि याचिकाकर्ता की दो साल की सेवा पूरी होने से बहुत पहले, पांचवें प्रतिवादी की शिकायत पर उसके विरुद्ध कार्यवाही शुरू कर दी गई थी, और राज्यपाल (विश्वविद्यालय के कुलाधिपति) ने प्रबंधन बोर्ड को एक विशेष बैठक आयोजित करने और पांचवें प्रतिवादी द्वारा याचिकाकर्ता के विरुद्ध लगाए गए आरोपों पर निर्णय लेने का निर्देश दिया था।इसलिए याचिकाकर्ता का स्थायी कर्मचारी होने का दावा मान्य नहीं है और स्थायी कर्मचारियों के संबंध में विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा दिए विद्वान निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होते हैं।

II. <u>क्या याचिकाकर्ता की सेवाओं को एक दंडात्मक और कलंकित आदेश द्वारा समाप्त किया जा सकता था?</u>

35 . श्री C.DI बहुगुणा, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रस्तुत करेंगे कि दिनांक 2 के आक्षेपित आदेश में दर्ज किया विद्वान निष्कर्ष, कि याचिकाकर्ता नैतिक अधमता के कार्य में शामिल था, दंडात्मक और कलंकित है; याचिकाकर्ता के विरुद्ध इस आरोप के नागरिक और बुरे परिणाम हैं, और इस तरह याचिकाकर्ता का पूरा सेवा जीवन बर्बाद हो विद्वान है; याचिकाकर्ता ने विशेष रूप से अनुरोध किया है कि, यदि नियोक्ता किसी अस्थायी कर्मचारी या परिवीक्षाधीन की सेवाओं को नागरिक या बुरे परिणामों वाले दंडात्मक या कलंकित आदेश द्वारा समाप्त करना चाहता है या चुनता है, तो नियोक्ता पर उसे सेवा से समाप्त करने से पहले उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करना अनिवार्य है; क्योंकि याचिकाकर्ता को दंडात्मक और साथ ही कलंकित आदेश द्वारा सेवा से हटा दिया विद्वान है। विश्वविद्यालय के प्रबंधन बोर्ड द्वारा हटाए जाने के आक्षेपित आदेश को दूषित कर दिया विद्वान था; जहां किसी व्यक्ति को नियोक्ता द्वारा अनुशासनात्मक जांच किए बिना दंडात्मक या कलंकित आदेश द्वारा सेवा से बर्खास्त या हटा दिया जाता है, तो स्वाभाविक परिणाम यह है कि आक्षेपित आदेशों को अपास्त कर दिया जाता है, और कर्मचारी को सेवा की निरंतरता सहित सभी परिणामी लाभों के साथ सेवा में फिर से स्थापित किया जाता है; और इसलिए, दिनांकित 04-04-2018 के आक्षेपित दंड आदेश को अपास्त कर दिया जाना चाहिए और अपास्त कर दिया जाना चाहिए। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, **(i) जगदीश मित्तरो 6; (ii) इंद्र पाल गुप्ता 4 ; (iii) प्रोग्रेसिव एजुकेशन सोसाइटी 1 8 ; (iv) शमशेर सिंह 2 ; (v) नर सिंह पाल 16** पर भरोसा किया।

36. इस संदर्भ में यह ध्यान दें आवश्यक है कि उच्चतम न्यायालय ने याचिकाकर्ता की ओर से दिए गए निर्णयों में कहा है कि अनुच्छेद 311 के संरक्षण का उपयोग न मात्र स्थायी लोक सेवकों द्वारा किया जा सकता है, बल्कि उन लोक सेवकों द्वारा भी किया जा सकता है जो अस्थायी सेवकों या परिवीक्षाधीनों के रूप में कार्यरत हैं।(**परशोतम लाल ढींगरा 1; जगदीश मित्तर 6 ")**।यदि सरकार परिवीक्षाधीन की ईमानदारी या क्षमता पर कोई संदेह किए बिना सीधे तरीके से उसके विरुद्ध आगे बढ़ती है, तो उसके आरोपमुक्त होने से सजा के रूप में हटाने का प्रभाव नहीं पड़ेगा।आसान रास्ता अपनाने के बजाय, अगर सरकार उनके विरुद्ध कार्यवाही शुरू करने का अधिक कठिन रास्ता चुनती है, और उन्हें एक बेईमान और अक्षम अधिकारी के रूप में ब्रांडिंग करती है, तो इसका दंड का प्रभाव होगा।**(गोपी किशोर प्रसाद 19**)।अस्थायी सेवक की सेवाओं की समाप्ति, जो अनुबंध की शर्तों या प्रासंगिक नियम के से उसके निर्वहन से अधिक नहीं है, को कानूनी रूप से उसकी बर्खास्तगी नहीं माना जा सकता है, क्योंकि नियुक्ति प्राधिकरण इस उद्देश्य से प्रेरित था कि उक्त सेवक किसी कथित कदाचार के लिए बने रहने के योग्य नहीं था।(**परशोतम लाल ढींगरा 1; जगदीश मित्तर6 ")**।नियुक्ति प्राधिकरण को परिवीक्षाधीन की सेवाओं को समाप्त करने की स्वतंत्रता है यदि वह परिवीक्षाधीन की अवधि के दौरान परिवीक्षाधीन के प्रदर्शन को असंतोषजनक पाता है।मूल्यांकन स्वयं नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा किया जाना चाहिए और संतुष्टि उसकी है। जब तक समाप्ति के साथ कोई कलंक नहीं जोड़ा जाता है, या परिवीक्षाधीन को किसी भी कमी का कारण दिखाने के लिए नहीं कहा जाता है जो बाद में परिवीक्षाधीन की सेवाओं को समाप्त करने का कारण हो सकता है, तब तक नियुक्ति प्राधिकरण को सेवाओं को समाप्त करने के लिए कोई स्पष्टीकरण या कारण देने की आवश्यकता नहीं है, सिवाय इसके कि उसे सूचित किया जाए कि उसकी सेवाएं असंतोषजनक पाई गई हैं।**(प्रगतिशील शिक्षा सोसायटी 18**)।उच्चतम न्यायालय के सभी निर्णय याचिकाकर्ता की ओर से निर्भर थे, और जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट किया गया है, एक कर्मचारी की नियुक्ति के पश्चात और परिवीक्षा की अवधि के दौरान उसके आचरण से संबंधित हैं।उपरोक्त निर्णयों में उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियों को संदर्भ से बाहर नहीं पढ़ा जा सकता है या उन मामलों में लागू नहीं किया जा सकता है जहां किसी व्यक्ति ने अपने आवेदन पत्र में सामग्री और प्रासंगिक तथ्यों को छिपाते हुए रोजगार प्राप्त किया है।

37. चूंकि याचिकाकर्ता की सेवाओं को समाप्त कर दिया गया था, प्रतिवादी विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर (आनुवंशिकी और पादप प्रजनन) के रूप में नियुक्ति की मांग करने वाले उसके आवेदन पत्र में तथ्यों को छिपाने और गलत तरीके से प्रस्तुत करने के अपास्त, विवादित आदेश को न तो उसके रोजगार के बाद सजा के उपाय के रूप में पारित किया गया कहा जा सकता है, न ही याचिकाकर्ता यह दावा कर सकता है कि समाप्ति के उक्त आदेश को इस आधार पर अलग करने की आवश्यकता है कि यह दंडात्मक या कलंकित है।प्रत्यर्थी-विश्वविद्यालय के प्रबंधन बोर्ड के लिए उसकी सेवाओं को समाप्त करने की शक्ति का स्रोत, याचिकाकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित आवेदन पत्र के घोषणा भाग का खंड (ए) है।इसमें विशेष रूप से यह प्रावधान किया गया है कि यदि आवेदन पत्र में कोई प्रविष्टि झूठी या गलत पाई जाती है, या यदि कुछ छिपा हुआ पाया जाता है, तो आवेदक को चयन के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, या यदि नियुक्त किया जाता है तो बिना किसी सूचना या मुआवजे के उसे समाप्त कर दिया जाएगा।केवल यह तथ्य कि दिनांकित 04.04.2018 के आक्षेपित आदेश में **"एक ऐखंड कार्य का करना जिसमें बोर्ड की मत में नैतिक अधमता शामिल है"** और "**खंडवा खंड हटा दिया गया है**" शब्दों का उपयोग किया गया है और विश्वविद्यालय अधिनियम के अध्याय 25 की धारा 4 (डी) (1) को गलत तरीके खंड संदर्भित किया गया है, दंड के आदेश को दूषित नहीं करेगा।यदि कोई कार्य करने या आदेश पारित करने की शक्ति का पता किसी सक्षम प्रावधान से लगाया जा सकता है, तो भले ही उस प्रावधान को विशेष रूप से संदर्भित नहीं किया गया हो (या किसी गलत प्रावधान के लिए गलत संदर्भ दिया गया हो), अधिनियम या आदेश को सक्षम प्रावधान के से किया गया या बनाया गया माना जाएगा।**(मेसर्स पाइन केमिकल्स लिमिटेड और Ors.20)**। आक्षेपित आदेश में एक गलत प्रावधान का संदर्भ, या उस प्रावधान को संदर्भित करने में विफलता जो सजा देने की शक्ति प्रदान करती है, इसलिए याचिकाकर्ता की सेवाओं को समाप्त करने के लिए शक्ति के स्रोत के रूप में सजा के आदेश को दूषित नहीं करेगी, निर्धारित आवेदन पत्र के घोषणा खंड में पता लगाया जा सकता है।

38. जिस स्थिति में याचिकाकर्ता खुद को पाता है, वह उसकी खुद की बनाई हुई है।चूंकि प्रबंधन बोर्ड द्वारा उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है, उनके आवेदन पत्र में तथ्यों को छिपाने, दबाने और गलत तरीके से प्रस्तुत करने के लिए, विश्वविद्यालय

में रोजगार की मांग करने के लिए, यह तर्क कि उनका पूरा सेवा जीवन बर्बाद हो गया है, अपने आप में और बिना किसी और चीज़ के, दिनांकित 04.04.2018 के विवादित आदेश में हस्तक्षेप को उचित नहीं ठहराएगा।याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए निर्णयों में यह तर्क दिया गया है कि एक परिवीक्षाधीन की सेवाओं को भी अनुशासनात्मक जांच के पश्चात दंडात्मक और कलंकित आदेश द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता है, मात्र उन मामलों में लागू होता है जहां एक कर्मचारी की सेवाओं को परिवीक्षा की अवधि के दौरान उसकी ओर से कदाचार के कृत्यों के लिए समाप्त किया जाता है, न कि नियुक्ति की मांग करने वाले उसके आवेदन पत्र में प्रासंगिक और भौतिक तथ्यों को दबाने और गलत तरीके से प्रस्तुत करने के उसके कार्य के लिए।नियुक्ति की मांग करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में प्रासंगिक और भौतिक तथ्यों को छिपाने/गलत तरीके से प्रस्तुत करने/दबाने और नियुक्ति के पश्चात किए गए कदाचार के कृत्यों (या तो परिवीक्षा के दौरान या पुष्टि के पश्चात) के बीच का अंतर हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए।

39. प्रश्न यह है कि क्या ऐसे मामलों में अनुशासनात्मक जांच की आवश्यकता है जहां किसी कर्मचारी की सेवाओं को नौकरी की मांग करने वाले उसके आवेदन पत्र में भौतिक तथ्यों को दबाने/गलत तरीके से प्रस्तुत करने के लिए समाप्त कर दिया जाता है, अब पूर्ण रूप से एकीकृत नहीं है। **कोनेटी वेंकटेश्वरुलु और Ors. 21** में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहाः

> ‘’.. हम प्रथम प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता के तर्क को प्रतिग्रहण करना करने में असमर्थ हैं।जहाँ तक उस उद्देश्य की बात है जिसके लिए जानकारी मांगी जाती है, नियोक्ता अंतिम न्यायाधीश होता है।यह उम्मीदवार के लिए खुला नहीं है कि वह मांगी गई जानकारी की प्रासंगिकता के बारे में निर्णय में बैठे और इसे प्रदान करने या न करने का निर्णय ले।इसमें कोई संदेह नहीं है कि आवेदन में कॉलम 11 के माध्यम से पूर्ण रोजगार विवरण की मांग की गई थी।इसी तरह, संलग्नक III में किसी भी सार्वजनिक या निजी रोजगार में काम नहीं करने की एक स्पष्ट घोषणा शामिल थी।हम इस तर्क को भी प्रतिग्रहण करना करने में असमर्थ हैं कि यह असावधानी थी जिसके कारण प्रथम प्रतिवादी ने कॉलम 11 में विवरण को खाली छोड़ दिया और आवेदन के संलग्नक III में गैर-रोजगार की घोषणा की। आवेदन 24.7.1999 पर भरा गया था, परीक्षा 24.10.1999 पर आयोजित की गई थी, और साक्षात्कार कॉल 31.1.2000 पर दिया गया था।किसी भी समय प्रथम प्रतिवादी ने अपीलकर्ता आयोग को सूचित नहीं किया कि आवेदन पत्र भरने में उनके द्वारा एक वास्तविक गलती हुई थी, या ऐसा करने में उनकी ओर से असावधानी थी।यह मात्र तब होता है जब अपीलकर्ता आयोग को स्वयं पता चलता है कि आवेदन में प्रथम प्रतिवादी की ओर से स्पष्टीकरण और सुझाव गलत थे कि प्रतिवादी एक बहाने के साथ आगे आया कि यह अनजाने में हुआ था।यह निर्विवाद है कि सबप्रेसो वेरी और सजेशियो फाल्सी हुआ है।यह स्पष्टीकरण कि यह अप्रासंगिक था या अनजाने में उत्पन्न हुआ, अस्वीकार्य है।हमारे विचार में, अपीलकर्ता को केंद्रीय विद्यालय संगठन (उपरोक्त) के अनुपात पर भरोसा करना और यह तर्क देना उचित था कि एक व्यक्ति जो इस तरह के दमनकारी कृत्यों में लिप्त है और झूठे ढोंग से रोजगार प्राप्त करता है, वह किसी भी सार्वजनिक रोजगार के योग्य नहीं है।हम इस दृष्टिकोण का पूरी तरह से समर्थन करते हैं....... "(जोर दिया गया)

40. **आर. राधाकृष्णन 22** में सर्वोच्च न्यायालय ने कहाः

> ‘’...... निर्विवाद रूप से, अपीलकर्ता का इरादा एक वर्दीधारी सेवा में नियुक्ति प्राप्त करने का था।ऐसी सेवा में सेवा करने का इरादा रखने वाले व्यक्ति से अपेक्षित मानक उस व्यक्ति से अलग है जो अन्य सेवाओं में सेवा करने का इरादा रखता है।नियुक्ति और सत्यापन सूची के लिए आवेदन हिंदी और अंग्रेजी दोनों में थे।इसलिए, वह एक महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा करने के लिए अपने बयान या चूक के निहितार्थ को जानते और समझते थे।तथ्य यह है कि इस तरह का खुलासा किए जाने की स्थिति में, प्राधिकरण उनके चरित्र को सत्यापित कर सकता था और नियुक्ति की उपयुक्तता भी विवाद में नहीं है।यह भी विवाद में नहीं है कि जिन व्यक्तियों ने इस तरह के खुलासे नहीं किए थे और इस प्रकार, समान रूप से स्थित थे, उन्हें नियुक्त नहीं किया गया था।

यह प्रश्न **दिल्ली प्रशासन में मुख्य सचिव और अन्य बनाम सुशील कुमार [(1996) 11 एस. सी. सी. 605]** के माध्यम द्वारा इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया, जिसमें इद्वारा स्पष्ट रूप द्वारा अभिनिर्धारित किया गया थाः

''.. न्यायाधिकरण ने विवादित आदेश में आवेदन को इस आधार पर स्वीकार कर लिया कि चूंकि प्रतिवादी को भा.दं.सं. सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 324 और भा.दं.सं. सी. की धारा 324 के से दंडनीय अपराध खंड मुक्त कर दिया गया था और/या बरी कर दिया गया था, इसलिए उखंड राज्य के से पद पर नियुक्ति के अधिकार खंड वंचित नहीं किया जा सकता है।प्रश्न यह है कि क्या न्यायाधिकरण द्वारा लिया गया दृष्टिकोण कानूनी रूप से सही है?यह देखा गया है कि चरित्र और पूर्वजों का सत्यापन यह परीक्षण करने के लिए महत्वपूर्ण मानदंडों में से एक है कि क्या चयनित उम्मीदवार राज्य के से किसी पद के लिए उपयुक्त है।हालाँकि वह शारीरिक रूप से स्वस्थ पाए गए, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार उत्तीर्ण हुए और उन्हें अस्थायी रूप से चुना गया, उनके पूर्व अभिलेख के कारण, नियुक्ति प्राधिकरण ने अनुशासित बल में कांस्टेबल के रूप में इस तरह के अभिलेख वाले व्यक्ति को नियुक्त करना वांछनीय नहीं पाया।

मामले की पृष्ठभूमि में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को अनुचित नहीं कहा जा सकता है **टी. यस. वासुदेव नायर बनाम विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक और अन्य [1988 एस. सी. सी. 795]।** उक्त निर्णय, जैसा कि निर्णय से ही स्पष्ट होगा, उक्त मामले के विशेष तथ्यों और परिस्थितियों पर प्रस्तुत किया गया है और इसे एक बाध्यकारी मिसाल नहीं माना जा सकता है।

तत्काल मामले में, निर्विवाद रूप से, अपीलकर्ता ने एक भौतिक तथ्य को दबा दिया था।इस तरह के मामले में, हमारी मत है कि उनके पक्ष में न्यायसंगत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने का प्रश्न ही नहीं उठेगा.....

41. **बिपाद भंजन गायें 24** में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा प्रश्न रेलवे सुरक्षा बल नियम, 1987 के नियम 57 में नियुक्ति की तिथि से दो साल की साक्षीकरण अवधि के अभिलेख विस्तार के अधीन प्रावधान प्रश्नया गया है; नियम 67 में प्रावधान प्रश्नया गया है प्रश्न बल के एक नामांप्रश्नत सदस्य के रूप में नियुक्ति के अभिलेख चुनी गई सीधी भर्ती प्रश्नसी भी स्तर पर छुट्टी के अभिलेख उत्तरदायी है, यदि मुख्य सुरक्षा अधिकारी, लिखित रूप में दर्ज प्रश्नए जाने वाले कारणों से, बल के हित में ऐसा करना तब तक उचित समझता है जब तक प्रश्न भर्ती अपीलकर्ता औपचारिक रूप से बल में नियुक्त नहीं प्रश्नया जाता है; इन दो नियमों अपीलकर्ता पढ़ने से पता चलेगा प्रश्न जब तक एक भर्ती औपचारिक रूप से बल में नामांप्रश्नत नहीं होती है, तब तक उसकी नियुक्ति बेहद कमजोर होती है; यह स्वीकार प्रश्नया गया मामला है प्रश्न प्रतिवादी अभी भी अपनी सेवाओं अपीलकर्ता समाप्त करने के समय साक्षीकरण के से था।

42. अवतार सिंह 25 में, सर्वोच्च न्यायालय ने राय दीः

".........यद्यपि एक आपराधिक मामले में पदधारी को बरी नहीं किया गया है और विचारण विचाराधीन है, नियोक्ता को ऐसे पदधारी को नियुक्त नहीं करने या सेवाओं को समाप्त करने में उचित ठहराया जा सकता है क्योंकि दोषसिद्धि अंततः उसे नौकरी के लिए अनुपयुक्त बना सकती है और नियोक्ता को आपराधिक मामले के परिणाम तक इंतजार नहीं करना चाहिए।ऐसे मामले में गैर-प्रकटीकरण या गलत जानकारी जमा करना महत्वपूर्ण होगा और यह अपने आप में नियोक्ता के लिए उम्मीदवारी रद्द करने या सेवाओं को समाप्त करने का आधार हो सकता है।

धोखाधड़ी और गलत निरूपण एक लेन-देन को दूषित करता है और यदि जाली दस्तावेजों के आधार पर रोजगार प्राप्त किया गया है, जैसा कि **एम. भास्करन के मामले (उपरोक्त)** में देखा गया है, तो संदर्भ आदेश में यह भी देखा गया है कि यदि कोई नियुक्ति धोखाधड़ी से प्राप्त की गई थी, तो पदधारी को बिना कोई जांच किए समाप्त किया जा सकता है, यद्यपि हम एक शर्त जोड़ते हैं कि यदि कर्मचारी की पुष्टि हो जाती है, तो वह सिविल पद धारण करता है और उसे अनुच्छेद 311 (2) का संरक्षण प्राप्त होता है, सेवाओं को समाप्त करने से पहले उचित जांच की जानी चाहिए।जाली दस्तावेजों के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने के मामले में विचाराधीन नौकरी के लिए पदधारी की बहुत पात्रता पर प्रभाव पड़ता है, यद्यपि पूर्ववृत्तियों का सत्यापन उनकी योग्यता के रूप में अलग पहलू है अन्यथा विचाराधीन पद के लिए।धोखाधड़ी से प्राप्त प्रस्तुतीकरण आदेश नियोक्ता के विकल्प पर अमान्य हैं, यद्यपि इस आदेश में दमन या गलत जानकारी जमा करने के प्रभाव पर की गई चर्चा के आलोक में प्रश्न का निर्धारण किया जाना चाहिए।इसमें कोई संदेह नहीं है कि चरित्र और पूर्वजों का सत्यापन उपयुक्तता का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण मानदंडों में से एक है और नियोक्ता के लिए पदधारी के पूर्वजों का निर्णय करने के लिए खुला है, लेकिन अंतिम कार्रवाई सभी प्रासंगिक पहलुओं पर उचित विचार करने पर वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर आधारित होनी चाहिए।

'सामग्री' जानकारी के दमन से यह अनुमान लगाया जाता है कि जिसे दबाया जाता है वह 'मायने रखता है' हर तकनीकी या तुच्छ बात नहीं है।नियोक्ता को उम्मीदवारी रद्द आदेश या कर्मचारी की सेवाओं को समाप्त आदेश के लिए शक्तियों के प्रयोग में नियमों/निर्देशों पर उचित विचार आदेश पर कार्य करना होगा।यद्यपि एक व्यक्ति जिसने भौतिक जानकारी को दबा दिया है, वह नियुक्ति या सेवा में निरंतरता के लिए निरंकुश अधिकार का दावा नहीं कर सकता है, लेकिन उसे मनमाने ढंग से व्यवहार नहीं करने का अधिकार है और शक्ति का प्रयोग उचित तरीके से होना चाहिए जिसमें तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए।

किस मामले मे किस मानदंड को लागू किया जाना है, यह पद की प्रकृति पर निर्भर करता है, उच्च पद में सभी सेवाओं के लिए अधिक कठोर मानदंड शामिल होंगे, न कि मात्र समान सेवा के लिए।निचले पदों के लिए जो संवेदनशील नहीं हैं, कर्तव्यों की प्रकृति, उपयुक्तता पर दमन के प्रभाव पर संबंधित अधिकारियों द्वारा कर्तव्यों/सेवाओं के पद/प्रकृति पर विचार किया जाना चाहिए और विभिन्न पहलुओं पर उचित विचार करने पर शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए।

'मैकार्थीवाद' संवैधानिक लक्ष्य के विपरीत है, उपयुक्त मामलों में युवा अपराधियों को सुधार का अवसर दिया जाना चाहिए, सुधारवादी सिद्धांत की परस्पर क्रिया को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है और न ही इसे आम तौर पर लागू किया जा सकता है, लेकिन उम्मीदवारी को रद्द करने या किसी कर्मचारी को सेवा से मुक्त करने की शक्ति का प्रयोग करते समय ध्यान में रखे जाने वाले कारकों में से एक है। गलत जानकारी देने के लिए सेवाओं की समाप्ति या उम्मीदवारी को रद्द करने का आदेश पारित करते समय, नियोक्ता ऐसी जानकारी देते समय मामले की विशेष परिस्थितियों, यदि कोई हो, पर ध्यान दे सकता है।

.... यदि कर्मचारी की सेवा में पुष्टि हो जाती है, तो दमन या सत्यापन प्रपत्र में गलत जानकारी जमा करने के आधार पर समाप्ति/निष्कासन या बर्खास्तगी का आदेश पारित करने से पहले विभागीय जांच करना आवश्यक होगा।....

दमन या गलत जानकारी का निर्धारण करने के लिए प्रमाणन/सत्यापन प्रपत्र विशिष्ट होना चाहिए, अस्पष्ट नहीं।मात्र ऐसी जानकारी का खुलासा किया जाना चाहिए जिसका विशेष रूप से उल्लेख किया जाना आवश्यक था।यदि माँगी गई लेकिन प्रासंगिक जानकारी नियोक्ता के ज्ञान में आती है, तो फिटनेस के प्रश्न को संबोधित करते समय उसी पर वस्तुनिष्ठ तरीके से विचार किया जा सकता है।हालाँकि, ऐसे मामलों में दमन या

गलत जानकारी प्रस्तुत करने के आधार पर कार्रवाई नहीं यद्यपि जा सकती है क्योंकि एक तथ्य जिसके लिए पूछा भी नहीं गया था।

(जोर दिया गया)

43. एक कर्मचारी को साक्षीकरण प्रपत्र के से जानकारी प्रस्तुत करने की आवश्यकता का उद्देश्य सेवा में निरंतरता के लिए उसके चरित्र और पूर्ववृत्त का आकलन करना है।जहां किसी कर्मचारी (परिवीक्षाधीन) से अपनी नियुक्ति के संबंध में (या तो उस समय या उसके बाद) साक्षीकरण प्रपत्र में अपना व्यक्तिगत डेटा देने की आवश्यकता होती है, यदि यह पाया जाता है कि कर्मचारी ने उन मामलों के संबंध में गलत जानकारी दी थी या गलत जानकारी दी थी जिसका उसकी योग्यता या पद के लिए उपयुक्तता पर असर पड़ा था, तो उसे बिना कोई जांच किए परिवीक्षा की अवधि के दौरान सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है।भौतिक जानकारी का दमन, और आवेदन पत्र में प्रश्नों के उत्तर में गलत बयान देना, नियोजित व्यक्ति के चरित्र, आचरण और पूर्ववृत्त पर स्पष्ट रूप से असर डालता है और इसलिए, नियोक्ता को परिवीक्षा की अवधि के दौरान अपनी सेवा समाप्त करने के लिए उचित माना जाएगा।**(राम रतन यादव 26; कमल नयन मिश्रा 27)**।यद्यपि राज्य से सिविल पद धारण करने वाले एक पुष्ट कर्मचारी को उसके विरुद्ध आरोपों को पूरा करने का अवसर दिए बिना, साक्षीकरण प्रपत्र में गलत जानकारी देने के लिए सेवा से बर्खास्त नहीं किया जा सकता है।**(राम रतन यादव 26)**।

44. श्री C.D। विद्वत वरिष्ठ अधिवक्ता बहुगुणा प्रस्तुत करेंगे कि प्रतिवादी द्वारा, **बीपाद भजन गायें 24 पर**, यह प्रस्तुत करने के लिए दी गई अवलम्ब कि आवेदन पत्र में तथ्य को छिपाने के आधार पर एक अस्थायी कर्मचारी/परिवीक्षाधीन की सेवाओं को समाप्त किया जा सकता है, गलत है; उक्त मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने दो पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आरोपमुक्त करने के आदेश का समर्थन किया, पहला उम्मीदवार एक जघन्य अपराध में शामिल था; दूसरा, विभाग ने समाप्ति आदेश में उस पर कोई कलंक नहीं डाला; याचिकाकर्ता की तुलना ऐसे उम्मीदवारों से नहीं की जा सकती जो जघन्य अपराधों में शामिल थे; 5वें प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री विनय कुमार द्वारा दिए विद्वान अधिकांश निर्णय गलत हैं क्योंकि वे उन उम्मीदवारों से संबंधित हैं जो **टी यस वासुदेव नायर 23,** उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि किसी व्यक्ति को सेवा से हटाने के लिए पिछली दोषसिद्धि का खुलासा न करना भी हमेशा एक कानूनी आधार नहीं हो सकता है; किसी मामले में संलिप्तता की गंभीरता मात्र एक प्रासंगिक तथ्य हो सकती है; और छोटे कृत्यों या अपराधों में शामिल व्यक्ति के साथ जघन्य अपराधों में शामिल व्यक्ति के समान व्यवहार नहीं किया जा सकता है; और याचिकाकर्ता को सेवा से हटाने के लिए पूरी कवायद, कानून में दूषित है।

45. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, सर्वोच्च न्यायालय ने **'बिपाद भजन गायें 24'** में यह अभिनिर्धारित किया है कि, जैसा कि नियोक्ता ने परिवीक्षा पर नियुक्ति दी थी, आवेदन पत्र में दिए गए तथ्यों के सत्यापन के अधीन, यदि जांच से पता चलता है कि दिए गए तथ्य गलत थे, तो कर्मचारी कर्मचारी की सेवाओं को समाप्त करने के लिए स्वतंत्र था; इस स्तर पर किसी भी कलंक और दंडात्मक परिणाम का प्रश्न उत्पन्न नहीं होगा; कर्मचारी की सेवाओं को समाप्त करने का कारण यह था कि उसने अपने आवेदन पत्र में प्रासंगिक जानकारी को रोक दिया था; और छल और छल में पैदा हुई सेवा को बर्दाशत नहीं किया जा सकता है।जैसा कि विस्तार से बताया जाएगा, बाद में इस आदेश में, याचिकाकर्ता ने अपने आवेदन पत्र में भौतिक तथ्यों को छुपाया/गलत तरीके से प्रस्तुत किया और दबा दिया। उन्होंने यह भी दबाया और गलत तरीके से प्रस्तुत किया कि उन्हें अपनी पीएचडी परीक्षा में अनुचित साधनों का सहारा लेने के लिए दो सेमेस्टर के लिए अस्थायी बर्खास्तगी की सजा दी गई थी, जिसमें उन्हें हाथ से लिखी चिट्स के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया था।एक व्यक्ति, जिसे उसकी परीक्षा में धोखाधड़ी करते हुए पाया गया था, शायद ही उसके छात्रों के लिए एक मॉडल के रूप में काम कर सकता है, अगर उसे प्रतिवादी विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के रूप में जारी रखा गया होता।

46. **T.S. वासुदेव नायर 23**, जिस पर याचिकाकर्ता की ओर से अवलम्ब रखा गया है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उस मामले के विशेष तथ्यों और परिस्थितियों में, यह महसूस किया गया कि अपीलकर्ता को केवल इस आधार पर नौकरी से

वंचित नहीं किया जाना चाहिए था कि उसने यह खुलासा नहीं किया था कि आपातकाल के दौरान, उसे एक अवसर पर नारे लगाने के लिए भारत रक्षा नियमों के से दोषी ठहराया गया था।

47. श्री C.D द्वारा रखा विद्वान अवलम्ब। बहुगुणा, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, उपरोक्त निर्णय पर, **T.S. वसुधावन नायर 23**, गलत स्थान पर है।**आर. राधाकृष्णन 22** में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि **वासुदेव नायर 23** में निर्णय, जैसा कि निर्णय से ही स्पष्ट था, उक्त मामले के विशेष तथ्यों और परिस्थितियों पर दिया गया था और इसे एक बाध्यकारी मिसाल नहीं माना जा सकता था।उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों के आलोक में याचिकाकर्ता की सेवाओं (या तो एक परिवीक्षाधीन के रूप में या विश्वविद्यालय अधिनियम 07.12.2015 की नियुक्ति के अनुबंध के संदर्भ में एक अस्थायी कर्मचारी के रूप में, और जिनकी सेवाओं की पुष्टि नहीं हुई थी) को अनुशासनात्मक जांच किए बिना, नियुक्ति के लिए 18.06.2015 पर उसके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में भौतिक तथ्यों को छिपाने/दबाने के लिए समाप्त किया जा सकता है।श्री C.D का प्रस्तुतीकरणकरण। बहुगुणा, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, कि ऐसी परिस्थितियों में अनुशासनात्मक जांच करने में विफलता घातक है, स्वीकृति के योग्य नहीं है।

48. यह तर्क कि प्रबंधन बोर्ड को याचिकाकर्ता के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करनी चाहिए थी, और ऐसा करने में इसकी विफलता के परिणामस्वरूप पेटेंट अवैध हो गया है, मात्र खारिज किए जाने के लिए ध्यान देने योग्य है। जैसा कि यहाँ ऊपर उल्लेख किया गया है, याचिकाकर्ता की सेवाओं की पुष्टि करने या 07.12.2017 पर दो साल की सेवा पूरी करने पर उसे दो साल की परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी करने की घोषणा करने का कोई आदेश पारित नहीं किया गया था।प्रत्यर्थी-विश्वविद्यालय के अधिनियम के नियम 4 (सी) के संदर्भ में, और दिनांकित नियुक्ति समझौते के खंड 4 के संदर्भ में, याचिकाकर्ता को या तो परिवीक्षाधीन के रूप में जारी रखा जाना चाहिए, या प्रत्यर्थी-विश्वविद्यालय का एक अस्थायी कर्मचारी होना चाहिए, जब तक कि उसकी सेवाओं को समाप्त करने पर विवादित आदेश पारित नहीं किया जाता है।चूंकि याचिकाकर्ता परिवीक्षा पर या एक अस्थायी कर्मचारी के रूप में बनी रही, और उसकी सेवाओं की समाप्ति 07.12.2015 पर प्रतिवादी-विश्वविद्यालय के साथ उसकी नियुक्ति के पश्चात उसकी ओर से किसी भी कदाचार के लिए नहीं थी, बल्कि उसके लिए सामग्री और प्रासंगिक तथ्यों को छिपाने और अपने आवेदन पत्र में तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने के लिए, प्रतिवादी-विश्वविद्यालय के लिए अपनी सेवाओं को समाप्त करने से पहले अनुशासनात्मक जांच करना पूरी तरह से अनावश्यक था।हम इस तर्क में कोई योग्यता नहीं देखते हैं कि विवादित आदेश को रद्द कर दिया जाना चाहिए और याचिकाकर्ता को सेवा की निरंतरता सहित सभी परिणामी लाभों के साथ सेवा में बहाल किया जाना चाहिए।

III. क्या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई प्रतिकूल आदेश पारित किया गया है?

49. श्री C.D। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, बहुगुणा प्रस्तुत करेंगे कि किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं विद्वान जा सकता है, जिसके नागरिक या बुरे परिणाम हैं, प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त का सख्ती से पालन किए बिना, और संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए बिना।विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता इस संबंध में **डॉ. बिनापानी देई 28; D.K यादव 29** पर भरोसा करेंगे। ।

50. इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसी व्यक्ति के निहित अधिकारों के हनन में उसके पूर्वाग्रह के लिए राज्य द्वारा आदेश मात्र न्यायाधीश और निष्पक्षता के बुनियादी नियमों के अनुसार ही दिया जा सकता है।निर्णायक प्राधिसेरी से कर्तव्य है कि वह उस व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध जांच की जाती है, अपना पक्ष या बचाव स्थापित करने से अवसर दे, और प्राधिकरण के कब्जे में किसी भी साक्ष्य को सुधारने या उससे खंडन करने से अवसर दे, जिस पर उसके पूर्वाग्रह पर भरोसा करने की कोशिश की जाती है।उस उद्देश्य के लिए, व्यक्ति को उस मामले के बारे में सूचित किया जाना चाहिए जिससे उसे मिलने के लिए बुलाया गया है, और उसके समर्थन में सबूत। यह नियम कि एक पक्ष जिसका पूर्वाग्रह एक आदेश पारित करने का इरादा है, सुनवाई का हकदार है, न्यायिक न्यायालय और नागरिक परिणामों से जुड़े मामलों पर निर्णय लेने के अधिकार के साथ निवेश किए गए व्यक्तियों के निकायों पर समान रूप से लागू होता है।यदि किसी व्यक्ति के पूर्वाग्रह को तय करने और

निर्धारित करने की शक्ति है, तो न्यायिक रूप से कार्य करने का कर्तव्य ऐसी शक्ति के प्रयोग में निहित है।यदि न्यायाधीश की अनिवार्यताओं को नजरअंदाज कर दिया जाता है, और किसी व्यक्ति के पूर्वाग्रह के लिए आदेश दिया जाता है, तो आदेश अमान्य है।**(डॉ. बिनापानी देई 28)**।

51. याचिकाकर्ता को नोटिस दिए जाने के पश्चात ही, उसे अपना जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया मात्र उसे सुनने का अवसर दिया गया, कुलाधिपति द्वारा उनके द्वारा पारित दिनांक 1 का आदेश था, जिसमें प्रबंधन बोर्ड को मामले की जांच करने का निर्देश दिया गया था।इससे पहले भी, याचिकाकर्ता को दिनांकित 30.01.2017 कार्यवाही के माध्यम से नोटिस पर रखा गया था, और उसे अपना जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था, जो उसने अपने दिनांकित 17.02.2017 पत्र द्वारा किया था।चूंकि दिनांक 04.04.2018 का विवादित आदेश कुलाधिपति द्वारा 14.09.2017 पर पारित आदेश के अनुसार पारित किया गया था, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता की सेवाओं को समाप्त करने वाला दिनांकित 04.04.2018 का उक्त आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए पारित किया गया था।इसलिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के बारे में विवाद मान्य नहीं है।

52. **D.K. यादव 29,** सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील फरीदाबाद में श्रम अदालत, हरियाणा के आदेश के विरुद्ध की गई थी, जिसमें कर्मचारी की सेवाओं की बर्खास्तगी को बरकरार रखा गया था।कंपनी के प्रमाणित स्थायी आदेशों में 8 दिनों के बाद अधिक के लिए स्वीकृत अवकाश की अवधि के बिना या उसके बाद अधिक की अभाव पर एक कर्मचारी की के बादवा को स्वचालित रूप के बाद समाप्त करने का प्रावधान किया गया है।बिना छुट्टी या पूर्व सूचना के 8 दिनों से अधिक समय तक ड्यूटी से अभाव के लिए उसकी सेवाओं को समाप्त करने पर, कर्मचारी ने तर्क दिया कि, 03.12.1980 पर ड्यूटी पर रिपोर्ट करने के बावजूद और उसके बाद लगातार हर दिन, उसे प्रवेश से रोक दिया गया और उपस्थिति रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने की अनुमति नहीं दी गई।D.K में एक विवाद था। यादव, इस बारे में कि कर्मचारी 8 दिनों से अधिक की अवधि के लिए बिना छुट्टी के ड्यूटी से अनुपस्थिति था या नहीं।इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्राकृतिक न्याय के नियमों का अनुपालन आवश्यक है और कर्मचारी को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाना चाहिए था। **D.K यादव 29** का वर्तमान मामले के तथ्यों पर कोई अनुप्रयोग नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ता को यहां नोटिस पर रखा गया था, और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति द्वारा सुनवाई का उचित अवसर दिया गया था।किसी भी स्थिति में, जैसा कि इस आदेश में बाद में विस्तृत किया जाएगा, याचिकाकर्ता द्वारा 18.06.2015 पर प्रस्तुत आवेदन पत्र में यह छिपाने के बारे में कोई विवाद नहीं है कि वह उस अवधि के दौरान बिहार कृषि विश्वविद्यालय में कार्यरत थी; और उसे अपनी Ph.D परीक्षा में हस्तलिखित चिट्स के साथ अनुचित साधनों का उपयोग करने के लिए दो सेमेस्टर के लिए अस्थायी बर्खास्तगी की सजा का सामना करना पड़ा था।

IV. <u>क्या याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर देने में प्रबंधन बोर्ड की विफलता घातक है?</u>

53. श्री C.D। बहुगुणा, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रस्तुत करेंगे कि दिनांक 04.04.2018 का विवादित आदेश, जिसमें प्रबंधन बोर्ड का संकल्प शामिल है, यह स्पष्ट करता है कि प्रबंधन बोर्ड ने याचिकाकर्ता को किसी भी आरोप के संबंध में किसी भी स्तर पर सुनवाई का अवसर नहीं दिया था; उसने पैरा को पुनः प्रस्तुत विद्वान था।कुलाधिपति के आदेश की धारा 5 ने अपने संकल्प में दिनांकित 14.09.2018 किया था, और याचिकाकर्ता के विरुद्ध लगाए गए आरोपों का पुनर्मूल्यांकन किया था, और फिर एकतरफा रूप से, याचिकाकर्ता को तुरंत सेवा से हटाने के निष्कर्ष पर पहुंचा था, जिससे याचिकाकर्ता का पूरा सेवा जीवन बर्बाद हो गया था; और जबकि रिट याचिका में इस संबंध में कथन किए गए हैं, विश्वविद्यालय ने अपने जवाबी-हलफनामे में रिट याचिका की सामग्री को अस्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया है।

54. चूंकि याचिकाकर्ता को कुलाधिपति द्वारा सुनवाई का अवसर दिया गया था, और कुलाधिपति की दिनांक 1 की कार्यवाही ने उस आधार का गठन किया जिसके आधार पर प्रतिवादी विश्वविद्यालय के प्रबंधन बोर्ड के प्रस्ताव के अनुसार समाप्ति का विवादित आदेश पारित किया गया था, इसलिए यह बहुत कम मायने रखता है कि याचिकाकर्ता को प्रबंधन बोर्ड द्वारा सुनवाई का दूसरा अवसर नहीं दिया गया था।अन्यथा भी, यह तथ्य कि याचिकाकर्ता ने बिहार कृषि विश्वविद्यालय में अपने रोजगार के तथ्य को दबाया/गलत तरीके से प्रस्तुत किया था, यह कहते हुए तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया

था कि उसे कोई सजा नहीं दी गई थी, और इस तथ्य को छिपाते हुए कि उसे दो सेमेस्टर के लिए अस्थायी बर्खास्तगी की सजा का सामना करना पड़ा था, विवाद में नहीं है। प्रबंधन बोर्ड को याचिकाकर्ता को नोटिस जारी करने और उसे सुनवाई का एक और अवसर देने का निर्देश, वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में जहां याचिकाकर्ता द्वारा अपने आवेदन पत्र में प्रासंगिक और भौतिक तथ्यों के दमन/छिपाने/गलत तरीके से प्रस्तुत करने के तथ्य विवाद में नहीं हैं, एक अनावश्यक औपचारिकता होगी, क्योंकि कोई अन्य परिणाम नहीं हो सकता था।

55. उच्च न्यायालय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के से कार्यवाही में, निरर्थक रिट जारी नहीं करेगा।संविधान के अनुच्छेद 226 के से एक याचिका को इस आधार पर खारिज किया जा सकता है कि एक रिट जारी करना अप्रभावी, निष्फल, अनावश्यक या निरर्थक होगा।यदि न्यायालय संतुष्ट है कि रिट जारी करने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा, तो वह केवल उसी आधार पर आवेदन को खारिज कर सकता है।चूंकि अर्थहीन रिट जारी करना न्यायालयों की प्रथा नहीं है, इसलिए राहत देते समय उच्च न्यायालय को इस बात पर विचार करना चाहिए कि रिट जारी करना अनावश्यक है या नहीं।**(सुरेश 30, बालमाडीज़ प्लांटेशन 31)**।जब भी परमादेश का एक रिट अपरिहार्य होगा, या यदि उसे निष्फल माना जाता है, तो उसे अस्वीकार करना कर दिया जाएगा।(**बाल कृष्ण अग्रवाल 32; अजीत कुमार एडी 33)।** सर्टिओरारी या परमादेश 9 की सरशियोरेराई तब जारी नहीं की जानी चाहिए जब वे बेकार हों।(**देबेंद्र बंधु लाहिरी 34; मेसर्स सिटको 35)।**

56. **S.L. कपूर 36** ने यह अभिनिर्धारित करते हुए कि विवादित आदेश को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने में विफलता के लिए दूषित किया गया था, सर्वोच्च न्यायालय ने मामले को वहीं रहने दिया और अधिसूचना को रद्द नहीं करने का फैसला किया क्योंकि समिति का कार्यकाल कुछ दिनों में समाप्त होने वाला था।

57. इसलिए, हम व्यर्थ रिट जारी करने का कोई कारण नहीं देखते हैं।

V. <u>याचिकाकर्ता के ओ. बी. सी. प्रमाणपत्र से संबंधित आरोपः</u>

58. श्री C.D। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता बहुगुणा प्रस्तुत करेंगे कि पहले दो आरोप, जैसा कि विवादित आदेश में उल्लेख किया विद्वान है, याचिकाकर्ता के ओ. बी. सी. प्रमाण पत्र से संबंधित हैं; विश्वविद्यालय ने अपने जवाबी शपथ पत्र में, रिट याचिका की सामग्री पर विवाद नहीं किया है; यहां तक कि 12 जुलाई 2016 के पत्र में, विश्वविद्यालय के मुख्य व्यक्तिगत अधिकारी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि याचिकाकर्ता वास्तव में ओ. बी. सी. श्रेणी से संबंधित है; याचिकाकर्ता का पैतृक घर बिहार राज्य के मऊ जिले में है, लेकिन याचिकाकर्ता का जन्म उत्तराखंड राज्य की क्षेत्रीय सीमाओं में हुआ था, और उसकी पूरी शिक्षा उत्तराखंड राज्य में थी; 'ओ. बी. सी. प्रमाण पत्र', 'जन्म प्रमाण पत्र', और 'स्थायी निवासी प्रमाण पत्र' उसे उत्तराखंड राज्य द्वारा जारी किया विद्वान था। आदेश, कि प्रत्येक व्यक्ति जो 15 वर्षों की अवधि से उत्तराखंड राज्य की क्षेत्रीय सीमाओं में रह रहा है, उस जिले से स्थायी निवासी प्रमाण पत्र प्राप्त करने का हकदार हो जाता है जहां वह रह रहा है।

59. हम श्री C.D के प्रस्तुतीकरण में काफी बल पाते हैं। बहुगुणा, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, कि चूंकि याचिकाकर्ता की ओ. बी. सी. के रूप में स्थिति विवाद में नहीं है, इसलिए समाप्ति का विवादित आदेश दिनांक 04.04.2018 , जिसमें उसके आवेदन पत्र के साथ हाल ही में जाति प्रमाण पत्र जमा करने में विफलता को घातक माना विद्वान है, अवैध है।याचिकाकर्ता ने अपना ओ. बी. सी. प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया था, और केवल यह तथ्य कि यह हाल ही में नहीं था, इसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता अन्य पिछड़े वर्गों का सदस्य नहीं रह जाएगा। दिनांकित 04.04.2018 का विवादित आदेश, जिस सीमा तक याचिकाकर्ता को हाल ही में जाति प्रमाण पत्र जमा नहीं करने का दोषी ठहराया गया था, अमान्य है।

VI. <u>अनुभव का दावा करने वाले याचिकाकर्ता से संबंधित आरोपः</u>

60. श्री C.D। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता बहुगुणा ने कहा कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध लगाया विद्वान पांचवां आरोप उसके दावे के अनुभव से संबंधित है जो सही नहीं था; यह आरोप अस्पष्ट है; जिस अनुभव के संबंध में यह

आरोप लगाया विद्वान है उसका कोई विवरण नहीं है; और विवादित आदेशों में इस पहलू पर कोई निष्कर्ष नहीं है, न ही विश्वविद्यालय ने इस अस्पष्ट आरोप पर कोई तर्क दिया है।

61. पांचवें प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री विनय कुमार द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तुतीकरण के बावजूद, याचिकाकर्ता को चयन समिति द्वारा अतिरिक्त अंक दिए गए हैं, जिसमें अनुभव भी शामिल है, हालांकि उसने कोई दावा नहीं किया था, हम याचिकाकर्ता की अंतर-योग्यता का तुलनात्मक मूल्यांकन करने और पांचवें प्रतिवादी की तुलना करने या यह निर्धारित करने का कोई कारण नहीं देखते हैं कि उनमें से कौन अधिक योग्य है। जबकि हम श्री C.D को प्रस्तुतीकरण करने के लिए सहमत हैं। बहुगुणा, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, कि यह आरोप विशिष्ट नहीं है, हमारे लिए इस पहलू पर अग्रेतर ध्यान देना अनावश्यक है, क्योंकि याचिकाकर्ता द्वारा अपने आवेदन पत्र में, उसके विद्या सम्बन्धी दंड का सामना करने के दमन के रूप में, और बिहार कृषि विश्वविद्यालय में उसकी नियुक्ति जब उसने प्रतिवादी-विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के पद के लिए आवेदन विद्वान था, अपने आप में, प्रतिवादी-विश्वविद्यालय के प्रबंधन बोर्ड की कार्रवाई को उसकी सेवाओं को समाप्त करने के लिए उचित ठहराएगी।

VII. <u>विद्या सम्बन्धी दंड से संबंधित आरोपः</u>

62. श्री C.D। बहुगुणा, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रस्तुत करेंगे कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध लगाया विद्वान तीसरा आरोप, विद्या सम्बन्धी दंड को छिपाने से संबंधित है; हालाँकि वर्ष 2012 में याचिकाकर्ता को उसका पीछा करते हुए विद्या सम्बन्धी दंड दिया विद्वान था। पाठ्यक्रम, विश्वविद्यालय की अनुशासन समिति की सिफारिश पर, विद्या सम्बन्धी परिषद ने अपनी बैठक में याचिकाकर्ता को आरोप से मुक्त कर दिया था, और 'परिवीक्षा संचालन' को हटा दिया था, और याचिकाकर्ता के विद्या सम्बन्धी पाठ्यक्रम के दौरान **'संतोषजनक आचरण'** जारी आदेश का निर्देश जारी किया था; कुलसचिव, G.B। पंत विश्वविद्यालय, पंतनगर ने 27-11-2014 पर याचिकाकर्ता को **'संतोषजनक आचरण'** का प्रमाण पत्र जारी किया; विश्वविद्यालय ने 18-12-2014 पर याचिकाकर्ता को Ph.D की अंक-पत्रक जारी की, जिसमें उसके आचरण को '**संतोषजनक**' बताया विद्वान; उसने Ph.D पाठ्यक्रम में 81.060% के उत्कृष्ट अंक प्राप्त किए; विश्वविद्यालय के मुख्य कार्मिक अधिकारी ने 12 जुलाई 2016 को कुलाधिपति के उप सचिव को संबोधित उत्तर पत्र में बताया कि एक विद्या सम्बन्धी दंड एक सुधारात्मक प्रक्रिया है और यह किसी भी छात्र को उच्च शिक्षा प्राप्त आदेश या किसी भी छात्र को कहीं भी रोजगार प्राप्त आदेश से वंचित आदेश से वंचित नहीं कर सकता है; याचिकाकर्ता के लिए अपने आवेदन पत्र में पिछले विद्या सम्बन्धी दंड का खुलासा नहीं आदेश का एक उचित औचित्य था।

63. प्रत्यर्थी-विश्वविद्यालय के कुलसचिव का दिनांकित कार्यालय आदेश 04.06.2012 इस प्रकार हैः

"पंजीकरण का कार्यालय

G.B. पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर-263 145, U.S.NAGAR (उत्तराखंड)

संख्या । आर. ई. जी./एस. ओ./डी. सी./2012/ 854 दिनांकः4 जून, 2012

कार्यालय आदेश

यह द्वितीय सेमेस्टर 2011-12 की सेमेस्टर अंतिम परीक्षा में अनुचितता के कथित उपयोग से उत्पन्न होने वाला मामला है।निरीक्षक डॉ. ओमवती, सहायक के माध्यम से एक रिपोर्ट दर्ज की गई।प्रोफेसर, कृषि विज्ञान से लेकर परीक्षा अधीक्षक।कॉलेज ऑफ बेसिक साइंस एंड ह्यूमैनिटीज और डीन C.B.S। & एच. कि सुश्री अनीता यादव, आईडी। नहीं। 30948, एक Ph. डी. स्कॉलर को "एएसटी-705 एडवांसेज इन सीड साइंस रिसर्च ऑन 15.05.2012 " पाठ्यक्रम में द्वितीय सेमेस्टर 2011-12 की अंतिम परीक्षा के दौरान हाथ से लिखी चिट्स के साथ अनुचितता का उपयोग करते हुए पाया गया था।डीन C.B.S। एंड एच ने सभी पत्रों के साथ मामले को विश्वविद्यालय अनुशासन समिति को भेज दिया।अनुशासन समिति ने मामले की जांच की और सुश्री अनीता यादव, आईडी को

भी बुलाया। 30948 पूछताछ के लिए जब उसने समिति के सामने स्वीकार किया कि उसके पास हाथ से लिखी पर्ची थी और निरीक्षक ने उसे पकड़ लिया था।

इस प्रकार, अनुशासन समिति के समक्ष छात्र के बयान और निरीक्षक द्वारा दर्ज की गई शिकायत से यह स्पष्ट है कि सुश्री अनीता यादव द्वितीय सेमेस्टर 2011-12 अंतिम परीक्षा में अन्याय का उपयोग करने की दोषी थीं।

इसलिए, अध्याय IV खंड 37 के से अन्याय के उपयोग पर विद्या सम्बन्धी विनियमन के अनुसार, अनुशासन समिति ने सुश्री अनीता यादव, आईडी नं 30948 "बीज विज्ञान अनुसंधान में ए. एस. टी.-705 प्रगति" पाठ्यक्रम में द्वितीय सेमेस्टर2011-12 अंतिम परीक्षा के दौरान अन्याय का उपयोग करने के लिए दोषी है और तदनुसार सुश्री अनीता यादव, आई. डी. नं. 30948 निम्न सजा की अनुशशा की जाती है

1. दो सेमेस्टर i.e के लिए अस्थायी बर्खास्तगी। द्वितीय सेमेस्टर 2011-12 और प्रथम सेमेस्टर 2012-13।

2. विश्वविद्यालय में उनके प्रवास के दौरान परिवीक्षा आयोजित करें।

कुलपति ने अनुशासन समिति की सिफारिश पर विचार करने के पश्चात मंजूरी दे दी है कि विश्वविद्यालय अनुशासन समिति द्वारा अनुशंसित सजा छात्र को दी जाए।

तदनुसार, सुश्री अनीता यादव, आईडी संख्या 30948 को विनियमों के अध्याय IV-खंड 37 के अनर्गत निम्नलिखित सजा दी जाती है।

1. दो सेमेस्टर i.e के लिए अस्थायी बर्खास्तगी। द्वितीय सेमेस्टर 2011-12 और प्रथम सेमेस्टर 2012-13।
2. विश्वविद्यालय में उनके प्रवास के दौरान परिवीक्षा आयोजित करें।

रजिस्टार "

64. 30.10.2014 पर आयोजित प्रत्यर्थी-विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् की 372वीं बैठक के कार्यवृत्त में याचिकाकर्ता और एक श्री रत्नाकर सिंह चौधरी के अनुरोध को दर्ज किया गया है, जिसमें परिवीक्षा संचालन को हटाने और संतोषजनक आचरण के साथ चरित्र प्रमाण पत्र जारी करने का अनुरोध किया गया है।यह इस संदर्भ में है कि प्रत्यर्थी-विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् ने संकल्प लिया कि अनुशासनात्मक समिति की सिफारिशों के अनुसार, याचिकाकर्ता और श्री रत्नाकर सिंह चौधरी के संबंध में परिवीक्षा संचालन को हटा दिया जाए और "संतोषजनक आचरण" के साथ आवश्यक दस्तावेज नियमों के अनुसार जारी किए जाएं।इसके बाद प्रत्यर्थी-विश्वविद्यालय के उप-पंजीयक द्वारा दिनांकित 27.11.2014 प्रमाण पत्र जारी किया गया, जिसमें प्रमाणित किया गया कि याचिकाकर्ता Ph.D (आनुवंशिकी और पादप प्रजनन) की डिग्री के लिए जुलाई, 2010 से मार्च, 2014 तक प्रत्यर्थी-विश्वविद्यालय की छात्रा थी, जिसे उन्होंने सफलतापूर्वक पूरा किया; और विश्वविद्यालय में अपने प्रवास की अवधि के दौरान, उनका आचरण संतोषजनक रहा था।

65. P.G याचिकाकर्ता के पक्ष में 18.12.2014 पर उप-पंजीयक द्वारा जारी प्रतिलिपि, उसके ग्रेड अंक दर्ज करती है।इसमें यह भी दर्ज किया गया है कि, अपने पहले सेमेस्टर 2010-11 और दूसरे सेमेस्टर 2010-11 और पहले सेमेस्टर 2011-12 से गुजरने के पश्चात उन्हें दूसरे सेमेस्टर 2011-12 और पहले सेमेस्टर 2012-13 के लिए अस्थायी रूप से अपनी पढ़ाई बंद करने की अनुमति दी गई थी और उन्होंने वर्ष 2011-12 और वर्ष के पहले सेमेस्टर 2012-13 से संबंधित अपना दूसरा सेमेस्टर, वर्ष 2013-14 में दूसरे सेमेस्टर के साथ पूरा किया और उसके पश्चात उन्होंने 01.02.2014 पर अपनी थीसिस प्रस्तुत की, और थीसिस के लिए वाइवा-वॉयस संतोषजनक परिणाम के साथ 26.03.2014 पर आयोजित किया गया।

66. याचिकाकर्ता की ओर से अवलम्ब ने विश्वविद्यालय द्वारा कुलाधिपति के उप सचिव को दिनांक 1 पर प्रस्तुत जवाब पर यह तर्क दिया कि विश्वविद्यालय ने यह भी माना था कि विद्या सम्बन्धी दंड मात्र एक सुधारात्मक प्रक्रिया थी, और किसी भी छात्र को कहीं भी रोजगार प्राप्त करने से वंचित नहीं करना चाहिए, यह पूरी तरह से गलत है।पाँचवें प्रतिवादी ने रिट याचिका दायर की (एस /बी) नहीं। 2016 का 156 याचिकाकर्ता की सहायक प्रोफेसर (आनुवंशिकी और पादप प्रजनन) के रूप में नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए, और उक्त रिट याचिका का निपटारा इस न्यायालय द्वारा अपने दिनांक 1 के आदेश द्वारा किया गया था, जिसमें कहा गया था कि याचिकाकर्ता के पास कुलाधिपति से संपर्क करने का वैकल्पिक उपाय था।इस न्यायालय ने निर्देश दिया कि सभी प्रभावित पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात कुलाधिपति द्वारा मामले पर जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए।प्रतिवादी नं. 5 ने कुलाधिपति को 18.06.2015 पर अपना अभ्यावेदन अभ्यावेदन किया जिसमें उन्होंने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने बिहार कृषि विश्वविद्यालय में अपनी पिछली नौकरी को छिपाकर रोजगार प्राप्त किया था, और उसे आचरण परिवीक्षा (CP) की सजा दी गई थी क्योंकि जब वह विश्वविद्यालय से अपना Ph.D पाठ्यक्रम कर रही थी तो उसे अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए पाया गया था।

67. इसके बाद ही कुलाधिपति के कार्यालय ने विश्वविद्यालय के कुलपति से पांचवें प्रतिवादी द्वारा लगाए गए आरोपों पर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए पत्र के माध्यम से कहा कि विश्वविद्यालय के अतिरिक्त मुख्य कार्मिक अधिकारी ने याचिकाकर्ता की सहायक प्रोफेसर (आनुवंशिकी मात्र पादप प्रजनन) के रूप में नियुक्ति का बचाव करते हुए अपना जवाब प्रस्तुत किया था।कुलाधिपति द्वारा 14.09.2017 पर एक आदेश पारित करने के पश्चात ही याचिकाकर्ता ने अपनी पिछली नौकरी के तथ्य को छिपाने के साथ-साथ उसे सजा दिए जाने के बारे में, मात्र विश्वविद्यालय के प्रबंधन मंडल को एक विशेष बैठक बुलाने मात्र उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया था, क्या प्रबंधन बोर्ड ने इस मामले पर विचार किया, जिसके परिणामस्वरूप 04.04.2018 का विवादित आदेश पारित किया गया, जिसमें याचिकाकर्ता की सेवाओं को समाप्त कर दिया गया।

68. जैसा कि प्रत्यर्थी-विश्वविद्यालय ने अपने दिनांक 3 दिनांकित पत्र में, याचिकाकर्ता को अवलम्ब प्रोफेसर (आनुवंशिपश्चात और पादप प्रजनन) के रूप में नियुक्त करने में अपनी कार्रवाई को उचित ठहराने पश्चात मांग पश्चात थी, और मामले पश्चात जांच प्रबंधन बोर्ड द्वारा मात्र तभी पश्चात गई थी जब कुलाधिपति ने इसे ऐसा करने का निर्देश दिया था।

69. राज्यपाल (विश्वविद्यालय के कुलाधिपति) का दिनांकित 14.09.2017 आदेश याचिकाकर्ता द्वारा अपने आवेदन पत्र में कुछ तथ्यों को छिपाने के अभ्यावेदन में पांचवें प्रतिवादी के अभ्यावेदन में आरोपों ध्यान दें देता है।इनमें ये आरोप शामिल हैं कि याचिकाकर्ता ने छिपाया था कि उद्वारा विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2012 में अनुचित साधनों के उपयोग के लिए दंडित किया गया था, और साथ ही उसकी पिछली नौकरी के लिए भी। वह उस समय बिहार कृषि विश्वविद्यालय की कर्मचारी थीं जब उन्होंने सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के लिए प्रत्यर्थी-विश्वविद्यालय को अपना आवेदन प्रस्तुत किया था और उन्होंने न तो उचित माध्यम द्वारा आवेदन किया था और न ही उन्हें बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया था।

70. कुलाधिपति के दिनांक 1 के उक्त आदेश में यह भी दर्ज किया गया है कि विश्वविद्यालय के साथ-साथ याचिकाकर्ता द्वारा पांचवें प्रतिवादी के अभ्यावेदन के संबंध में एक रिपोर्ट और जवाब मांगा गया था; और याचिकाकर्ता और पांचवें प्रतिवादी के साथ-साथ विश्वविद्यालय दोनों को सुनवाई का अवसर दिया गया था; याचिकाकर्ता को दी गई सुनवाई के दौरान, यह पता चला कि बिहार में उसके रोजगार के तथ्य का खुलासा उसने अपना आवेदन जमा करते समय नहीं किया था; आवेदन भी उचित माध्यम द्वारा नहीं किया गया था, और उसके पास नियोक्ता द्वारा एनओसी नहीं थी; दूसरा मुद्दा याचिकाकर्ता द्वारा अपनी परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का उपयोग करने का मामला था; इस बिंदु का भी कहीं उल्लेख नहीं किया गया था; चयन समिति इस पृष्ठभूमि द्वारा अनजान थी; और, भले ही संभावित मुद्रा का खुलासा किया गया था।

71. राज्यपाल (विश्वविद्यालय के कुलाधिपति) के उक्त आदेश में अग्रेतर लिखा गया है कि यदि चयन समिति को अनुचित साधनों के मामले, रोजगार को छिपाने और अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के बारे में पता होता, तो उन्होंने एक स्वच्छ और बेदाग रिकॉर्ड वाले अन्य उम्मीदवारों पर अपनी वरीयता नहीं दी होती; और एक व्यक्ति जो अनुचित साधनों का उपयोग करके परीक्षा में पकड़ा जाता है, जिसे उम्मीदवार द्वारा चुनौती नहीं दी जाती है, उससे शायद ही एक शिक्षक के रूप में दूसरों के लिए एक अच्छा उदाहरण होने की उम्मीद की जा सकती है; और आवेदन जांच प्रक्रिया जो इन सभी कारकों की पूरी तरह से अनदेखी करती है, और वास्तव में उन्हें छुपाती है और चयन समिति से दूर रखती है, वह आरम्भतः ही त्रुटिपूर्ण थी। राज्यपाल ने निर्देश दिया कि ऐसी परिस्थितियों में विश्वविद्यालय के कार्यपालक की एक विशेष बैठक i.e आयोजित की जाए। प्रबन्धन बोर्ड का गठन किया जाए और उपरोक्त तथ्यों को भी उचित निर्णय के लिए उनके समक्ष रखा जाए क्योंकि वे नियुक्ति प्राधिकरण थे।आदेश की तिथि से सात दिनों के भीतर उपरोक्त टिप्पणियों के आलोक में निर्णय लेने के लिए प्रबंधन बोर्ड की एक विशेष बैठक बुलाने का निर्देश दिया गया था।

72. यह तर्क, कि याचिकाकर्ता के लिए अपने आवेदन पत्र में पिछले विद्या सम्बन्धी दंड का खुलासा नहीं करने का उचित औचित्य था, और इस तरह का खुलासा समय के साथ महत्वहीन हो गया था, मान्य नहीं है।कॉलम, जिसे याचिकाकर्ता को आवेदन पत्र i.e भरने की आवश्यकता थी। कॉलम 10 (बी) में विशेष रूप से उन्हें यह बताने की आवश्यकता थी कि क्या उन्हें कभी विश्वविद्यालय द्वारा दंडित किया गया था।इस संबंध में, याचिकाकर्ता ने "नहीं" के रूप में जवाब दिया था।याचिकाकर्ता ने इस तथ्य को दबा दिया था कि उसे विश्वविद्यालय के कुलसचिव द्वारा दो सेमेस्टर के लिए अस्थायी बर्खास्तगी और विश्वविद्यालय में रहने के दौरान परिवीक्षा आयोजित करने की सजा दी गई थी।भले ही याचिकाकर्ता का यह तर्क कि विश्वविद्यालय विरुद्ध रहने के दौरान परिवीक्षा के संचालन सीमा तक सजा के आदेश को बाद विरुद्ध अपास्त दिया गया था और उसे अब उस सजा को संदर्भित करने की आवश्यकता नहीं थी जिसे अपास्त दिया गया है, स्वीकार कर लिया जाता है, याचिकाकर्ता को दो सेमेस्टर के लिए अस्थायी बर्खास्तगी का एक और दंड लगाया गया था, जिसे उसने बिना किसी आपत्ति के झेला था, और कॉलम नं। 10 (ख), कि उसे दो सेमेस्टर के लिए अस्थायी बर्खास्तगी की सजा दी गई थी, परीक्षा विरुद्ध अनुचित साधनों का उपयोग करने के लिए (परीक्षा विरुद्ध उसे हस्तलिखित चिट्स का उपयोग करते हुए पाए जाने पर), निस्संदेह, प्रासंगिक और भौतिक तथ्यों को छिपाने और गलत तरीके से प्रस्तुत करने के बराबर होगा।यह तर्क, कि विद्या सम्बन्धी दंड के तथ्य को छिपाना अनुशासनात्मक कार्यवाही किए बिना और एक कलंकित और दंडात्मक आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ता की सेवाओं को समाप्त करने के लिए एक कानूनी आधार नहीं है, मान्य नहीं है।जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, जहां परिवीक्षाधीन की सेवाओं को समाप्त कर दिया जाता है, किसी पद पर नियुक्ति के लिए उसके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में गलत तरीके से प्रस्तुत/दबाए गए/छिपे हुए तथ्यों के लिए कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है।इस शीर्ष के से विवाद भी अस्वीकृति की आवश्यकता है।

VIII. <u>क्या कुलाधिपति की याचिकाकर्ता को विद्या सम्बन्धी दंड के संबंध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर देने में विफलता घातक है?</u>

73. श्री C.D। बहुगुणा, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रस्तुत करेंगे कि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति ने याचिकाकर्ता द्वारा विद्या सम्बन्धी दंड के संबंध में आरोपों पर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए नहीं कहा; कुलाधिपति के कार्यालय ने, 30 जनवरी 2017 के पत्र के माध्यम द्वारा पांचवें प्रतिवादी द्वारा लगाए विद्वान आरोपों के बारे में विश्वविद्यालय के कुलपति की रिपोर्ट मांगते हुए, कुलपति द्वारा मात्र कुछ बिंदुओं पर याचिकाकर्ता द्वारा स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए कहा। आवेदन पत्र में उत्तर प्रदेश के स्थायी पते का उल्लेख होने के बावजूद, उसमें उत्तराखंड राज्य का उल्लेख करते हुए जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के औचित्य के संबंध में; विश्वविद्यालय के मुख्य व्यक्तिगत अधिकारी के 10 फरवरी 2017 के पत्र में स्पष्ट रूप द्वारा कहा गया है कि कार्यालय/सचिवालय के पत्र की एक प्रति संलग्न की गई थी, जिसका अर्थ है कि पांचवें प्रतिवादी का अभ्यावेदन याचिकाकर्ता को उक्त पत्र के साथ नहीं दिया गया था; हालांकि कुलाधिपति के कार्यालय के 30 जनवरी, 2017 के उक्त पत्र में याचिकाकर्ता को मात्र उत्तराखंड राज्य द्वारा जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के अपने कार्य को सही ठहराने की आवश्यकता थी, फिर भी याचिकाकर्ता ने उक्त पत्र में उठाए विद्वान सभी बिंदुओं पर विश्वविद्यालय के मुख्य व्यक्तिगत

अधिकारी के माध्यम द्वारा कुलाधिपति के समक्ष अपना विस्तृत स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया; कुलाधिपति के कार्यालय का पत्र।

74. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रस्तुत करेंगे कि याचिकाकर्ता, रिट याचिका में, विशेष रूप से अनुरोध किया है कि कुलाधिपति यह देखने में पूरी तरह से विफल रहे हैं कि, उनके कार्यालय द्वारा जारी किए गए दिनांकित कारणदर्शक पत्र में, याचिकाकर्ता के विरुद्ध अनुचित साधनों का उपयोग करने में शामिल होने का कोई आरोप नहीं था, और उनके द्वारा विद्या सम्बन्धी दंड के तथ्य को छिपाने के बारे में, और इसअभिलेख कुलाधिपति द्वारा याचिकाकर्ता को मिलने और इस तरह के आरोप की व्याख्या करने का कोई अवसर नहीं दिया गया था; याचिकाकर्ता को मिलने और उक्त आरोप की व्याख्या करने का अवसर न देना, और उक्त आरोप के विरुद्ध अपना बचाव करने का अवसर न देना, कुलाधिपति के 14-दिनांकित विवादित आदेश को प्रस्तुत करता है जो कानून में दूषित है; जवाब में, विश्वविद्यालय ने स्पष्ट रूप से दावों का खंडन नहीं किया है, और कहा है

75. प्रतिवादी-विश्वविद्यालय के मुख्य कार्मिक अधिकारी ने याचिकाकर्ता को दिनांकित पत्र 10.02.2017 के माध्यम से सूचित किया कि, पांचवें प्रतिवादी द्वारा अभ्यावेदन अभ्यावेदन पर, कुलाधिपति ने निर्देश दिया था कि, उक्त पत्र में उल्लिखित बिंदुओं के आलोक में, याचिकाकर्ता साक्ष्य के साथ अपना बचाव अभ्यावेदन कर सकती है।याचिकाकर्ता से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया था कि वह सात दिनों के भीतर विश्वविद्यालय के कार्यालय को लिखित रूप में अपना बचाव उपलब्ध कराए, ताकि इसे राज्यपाल/कुलाधिपति को भेजा जा सके।

76. याचिकाकर्ता के जवाब में, दिनांकित 17.02.2017 पत्र के माध्यम से, दिनांकित 10.02.2017 और 30.01.2017 पत्रों पर अपना बिंदुवार जवाब प्रस्तुत किया।उक्त दिनांकित 17.02.2017 पत्र में, याचिकाकर्ता ने न तो कुलाधिपति को पांचवें प्रतिवादी द्वारा अभ्यावेदन किए गए दिनांकित 18.05.2016 अभ्यावेदन की प्रति मांगी, और न ही उसने कहा कि वह इसकी सामग्री से अनजान थी।आई. डी. 3 दिनांकित अपने अभ्यावेदन में, पाँचवें प्रतिवादी ने विशेष अभ्यावेदन से कहा था कि विश्वविद्यालय ने इस तथ्य की अनदेखी या संज्ञान लेने में त्रुटि की थी कि याचिकाकर्ता ने इस बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य को छिपा दिया था कि जब वह विश्वविद्यालय से अपनी आई. डी. 4 का अध्ययन कर रही थी, तो उसे अपनी द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा आई. डी. 5 के दौरान हस्तलिखित चिट्स के साथ अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए पाया गया था, और आई. डी. 2 दिनांकित पत्र के अनुसार, दो सेमेस्टर आई. डी. 1 के लिए अस्थायी बर्खास्तगी का दंड लगाया गया था। द्वितीय सेमेस्टर 2011 12 और प्रथम सेमेस्टर 2012-13, और विश्वविद्यालय में उनके प्रवास के दौरान परिवीक्षा का संचालन करें।यह पहली बार है, लिखित याचिका (एस/बी) नं. उसके द्वारा दायर 2018 का 173 अब याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि उसे पाँचवें प्रतिवादी के दिनांकित पत्र की एक प्रति प्रस्तुत नहीं की गई थी और, यदि उसे इस तरह प्रस्तुत किया गया होता, तो वह उस पर लगाए गए आचरण परिवीक्षा के संबंध में अपना जवाब प्रस्तुत करती।

77. जबकि राज्यपाल के उप सचिव (विश्वविद्यालय के कुलाधिपति) द्वारा प्रतिवादी विश्वविद्यालय को संबोधित 30.01.2017 दिनांकित पत्र में, याचिकाकर्ता को दंड का सामना करने का उल्लेख नहीं किया गया है, जब वह प्रतिवादी-विश्वविद्यालय में अपना Ph.D. पाठ्यक्रम से गुजर रही थी, "बीज विज्ञान अनुसंधान में प्रगति" पाठ्यक्रम में 15.05.2012 पर अपनी द्वितीय सेमेस्टर 2011-12 अंतिम परीक्षा के दौरान हस्तलिखित चिट्स के साथ अनुचित साधनों का उपयोग करने के लिए, कुलाधिपति की दिनांक 14.09.2017 की कार्यवाही से यह स्पष्ट है कि उसके द्वारा याचिकाकर्ता, प्रतिवादी-विश्वविद्यालय और पांचवें प्रतिवादी को सुनवाई का अवसर दिया गया था।कुलाधिपति के दिनांक 14.09.2017 के उक्त आदेश में याचिकाकर्ता द्वारा अपनी जांच में अनुचित साधनों के उपयोग को दर्ज किया गया है, इस बिंदु का कहीं भी उल्लेख नहीं मिला है, चयन समिति इस पृष्ठभूमि से अनजान थी, और "भले ही कदाचार के लिए फटकार की सजा की संभावित मुद्रा समाप्त हो गई थी, लेकिन यह उम्मीदवार को नैतिक रूप से दोषमुक्त नहीं करता है।

78. कुलाधिपति की उपरोक्त टिप्पणियों से यह स्पष्ट है कि वह इस बात से अवगत थे कि याचिकाकर्ता को दो सेमेस्टर के लिए अस्थायी बर्खास्तगी की सजा दी गई थी। द्वितीय सेमेस्टर 2011-12 और प्रथम सेमेस्टर 2012-13, और विश्वविद्यालय में उनके प्रवास के दौरान परिवीक्षा का संचालन; और यह कि विद्या परिषद् ने 30.10.2014 पर आयोजित अपनी बैठक में उन्हें दोषमुक्त कर दिया था, "परिवीक्षा का संचालन" के आदेश को हटा दिया था और निर्देश दिया था कि उनके विद्या सम्बन्धी पाठ्यक्रम के लिए "संतोषजनक आचरण" का प्रमाण पत्र जारी किया जाए।यह तथ्य कि कुलाधिपति इतने जागरूक थे, उनके इस अवलोकन से मजबूत होता है कि यदि चयन समिति रोजगार को छिपाने और एन. ओ. सी. पेश न करने के अलावा अनुचित साधनों के मामले के उपयोग के बारे में जानती थी, तो उन्होंने एक स्वच्छ और बेदाग रिकॉर्ड वाले अन्य उम्मीदवारों पर अपनी वरीयता नहीं दी होगी; और एक व्यक्ति जो अनुचित साधनों का उपयोग करके परीक्षा में पकड़ा गया था, जिसे उम्मीदवार द्वारा चुनौती नहीं दी गई थी, शायद ही एक शिक्षक के रूप में दूसरों के लिए एक अच्छा उदाहरण होने की उम्मीद की जा सकती थी।

79. यह विवाद में नहीं है कि याचिकाकर्ता को दो सेमेस्टर के लिए अस्थायी बर्खास्तगी और परिवीक्षा आयोजित करने के लिए सजा के आदेश का सामना करना पड़ा, उसने दो सेमेस्टर के लिए अस्थायी बर्खास्तगी की सजा झेली। द्वितीय सेमेस्टर 2011-12 और प्रथम सेमेस्टर 2012-13।इसके बाद ही उन्होंने वर्ष 2012-13 के लिए द्वितीय सेमेस्टर पाठ्यक्रम पूरा किया, उसके बाद वर्ष 2013-14 के प्रथम सेमेस्टर मात्र द्वितीय सेमेस्टर पाठ्यक्रम, मात्र अंत में उन्हें 28.03.2014 पर Ph.D की अनंतिम डिग्री से सम्मानित किया गया।जबकि "आचरण परिवीक्षा" की सजा को निस्संदेह वापस ले लिया गया था, और विद्या परिषद् द्वारा 30.10.2014 पर आयोजित अपनी बैठक में "संतोषजनक आचरण" का प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया गया था, याचिकाकर्ता द्वारा अपना Ph.D. पाठ्यक्रम पूरा करने और 28.03.2014 पर एक अस्थायी Ph.D. डिग्री से सम्मानित किए जाने के लंबे समय पश्चात याचिकाकर्ता को दो सेमेस्टर के लिए अस्थायी बर्खास्तगी की दूसरी सजा, i.e का सामना करना पड़ा। द्वितीय सेमेस्टर 2011-12 और प्रथम सेमेस्टर 2012-13, बिना किसी आपत्ति के, और उक्त सजा हमेशा लागू रही है, और इसे कभी भी अपास्त या अलग नहीं किया गया था। कुलाधिपति के दिनांक 14.09.2017 के आदेश से यह स्पष्ट है कि वह याचिकाकर्ता पर लगाए गए दंड और दंड के एक हिस्से, i.e को निरस्त करने के बारे में जानते थे। परिवीक्षा आयोजित करें, "बाद में।

80. जैसा कि दिनांक 1 की कार्यवाही से पता चलता है कि कुलाधिपति इन सभी पहलुओं से अवगत थे, याचिकाकर्ता की ओर से आग्रह किया गया कि, यदि याचिकाकर्ता को एक अवसर दिया गया होता, तो वह "परिवीक्षा संचालन" की सजा को रद्द करने के तथ्य को लाती, और बाद में कुलाधिपति के नोटिस में उन्हें "संतोषजनक आचरण" का प्रमाण पत्र जारी किया गया था, जिसका कोई फायदा नहीं है।याचिकाकर्ता के विरुद्ध की गई कार्रवाई उसके लिए नहीं है कि उसने खुद सजा झेली है, बल्कि उसके लिए है कि वह अपने आवेदन पत्र में इन तथ्यों को बताने में विफल रही, जिसके परिणामस्वरूप चयन समिति को उसे सजा दिए जाने की जानकारी नहीं दी गई, और इस तथ्य को दबाने के लिए कि उसने सजा झेली है।

81. ऐसी परिस्थितियों में, प्रत्यर्थी-विश्वविद्यालय के मुख्य कार्मिक अधिकारी द्वारा अपनी दिनांकित कार्यवाही में विशेष रूप से विद्या सम्बन्धी दंड का उल्लेख करने में विफलता, जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता अपने दिनांकित उत्तर पत्र में उक्त दंड की व्याख्या करने में असमर्थ है, का कोई परिणाम नहीं है।इसमें कोई संदेह नहीं है कि कुलाधिपति ने अपनी दिनांकित कार्यवाही में याचिकाकर्ता के विरुद्ध आलोचनात्मक टिप्पणी की थी, जिसमें इस तथ्य को दबाना भी शामिल था कि वह बिहार कृषि विश्वविद्यालय में कार्यरत थी और उसे अपनी परीक्षा में "अनुचित साधनों" का उपयोग करने के लिए विद्या सम्बन्धी दंड का सामना करना पड़ा था।याचिकाकर्ता ने, उसके द्वारा दायर रिट याचिका सहित किसी भी कार्यवाही में, इस बात से इनकार नहीं किया है कि उसे दो सेमेस्टर के लिए अस्थायी बर्खास्तगी की सजा दी गई है, परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग करने के लिए और उसमें हस्तलिखित चिट्स का उपयोग करते हुए पाया गया है।प्रतिवादी विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर (आनुवंशिकी और पादप प्रजनन) के रूप में नियुक्ति के लिए 18.06.2015 पर दायर उनके आवेदन पत्र में इस तथ्य को भी दबाया गया है कि उन्होंने बिना किसी आपत्ति के उक्त सजा का सामना किया।

82. प्रत्यर्थी-विश्वविद्यालय के प्रबंधन बोर्ड ने 16.10.2017 पर आयोजित अपनी 232वीं बैठक में कहा कि याचिकाकर्ता को वर्ष 2012 में विश्वविद्यालय में रहने के दौरान अनुचित साधनों के उपयोग का दोषी पाया गया था और याचिकाकर्ता के आवेदन पत्र की जांच करने वाली कृषि महाविद्यालय की जांच समिति को वर्ष 2012 में याचिकाकर्ता द्वारा अनुचित साधनों के उपयोग के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए था।13.03.2018 पर आयोजित अपनी बाद की बैठक में, प्रबंधन बोर्ड ने नोट किया कि याचिकाकर्ता ने बिंदु संख्या पर तथ्यों को छुपाया था। 10 (ख) जिसमें उसे यह बताने की आवश्यकता थी कि क्या उसे कभी प्रत्यर्थी-विश्वविद्यालय द्वारा दंडित किया गया था, और "नहीं" शब्द लिखा था, हालांकि उस पर अतीत में पंजीयक के कार्यालय आदेश दिनांक 04.06.2012 द्वारा सजा का आरोप लगाया गया था।प्रबंधन बोर्ड ने उन तथ्यों ध्यान दें दिया है जो विवाद में नहीं हैं और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि याचिकाकर्ता ने अपने आवेदन पत्र के प्रासंगिक कॉलम में इस तथ्य को छिपा दिया था कि उसे सजा हुई थी।इसलिए प्रत्यर्थी-विश्वविद्यालय के प्रबंधन बोर्ड द्वारा याचिकाकर्ता की सेवाओं की समाप्ति को मनमानी या कानून में दूषित नहीं कहा जा सकता है।

IX. <u>रोजगार छिपाने से संबंधित आरोपः</u>

83. श्री C.D। बहुगुणा, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रस्तुत करेंगे कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध लगाया विद्वान चौथा आरोप, आवेदन पत्र में अपनी पिछली नौकरी को छिपाने, उचित माध्यम द्वारा पद के लिए आवेदन नहीं करने और बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा एन. ओ. सी. प्राप्त न करने द्वारा संबंधित है; चूंकि पिछली नौकरी के बारे में जानकारी प्रदान करने का प्रश्न उचित माध्यम द्वारा पद के लिए आवेदन करने की पूर्व शर्त के साथ जोड़ा विद्वान है, और पिछले नियोक्ता द्वारा एन. ओ. सी. प्राप्त करने के लिए, याचिकाकर्ता के पास आवेदन पत्र में 'लागू नहीं' के रूप में उल्लेख करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, इस सरल कारण द्वारा कि याचिकाकर्ता को पैरा में एक शर्त के साथ दो साल की अवधि के लिए परिवीक्षा पर <आई. डी. 1> दिनांकित नियुक्ति पत्र द्वारा बिहार कृषि विश्वविद्यालय में नियुक्त किया विद्वान था। नियुक्ति पत्र के 5 में कहा गया है कि परिवीक्षा अवधि के दौरान, उनकी द्वारावाओं को समाप्त किया जा सकता था; एक परिवीक्षाधीन होने के नाते, याचिकाकर्ता को इस पद पर तब तक कोई कानूनी अधिकार नहीं था जब तक कि वह कम द्वारा कम 2 साल की परिवीक्षा अवधि पूरी नहीं कर लेती; इसलिए, उद्वारा जून, 2015 के महीने में अपने नियोक्ता द्वारा अपना आवेदन पत्र G.B पर भेजने के लिए कहने का कोई निहित अधिकार नहीं था। पंत विश्वविद्यालय उचित माध्यम द्वारा, और उसके पक्ष में एक एन. ओ. सी. जारी करता है; विश्वविद्यालय का रुख, जैसा कि 12 जुलाई 2016 के पत्र में कुलाधिपति के समक्ष रखा गया है, यह है कि इस तथ्य का खुलासा न करना भौतिक नहीं था; यदि याचिकाकर्ता ने अपनी पिछली नौकरी का खुलासा किया होता, तो उद्वारा बिहार कृषि विश्वविद्यालय में अपने अनुभव के लिए कुछ और अंक मिलते; पिछली नौकरी का खुलासा न करना किसी भी भौतिक तथ्य को छिपाने के बराबर नहीं हो सकता है; और यह अनुशासनात्मक कार्यवाही किए बिना किसी व्यक्ति को कलंकित और दंडात्मक आदेश द्वारा द्वारावा द्वारा हटाने के लिए एक कानूनी आधार का गठन नहीं कर सकता है।

84. जैसा कि यहाँ ऊपर उल्लेख किया गया है, आवेदन पत्र में गलत तरीके से बताए गए और तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने का पूरा मुद्दा मात्र पांचवें प्रतिवादी द्वारा प्रतिवादी-विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के रूप में याचिकाकर्ता की नियुक्ति को चुनौती दिए जाने पर सामने आया।पाँचवें प्रतिवादी को दिनांकित 15.12.2015 पत्र के माध्यम से सूचित किया गया था कि याचिकाकर्ता ने 31.01.2015 से 05.12.2015 तक बिहार कृषि विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर (आनुवंशिकी और पादप प्रजनन) के रूप में काम किया था।दिनांक 15.12.2015 के उक्त पत्र से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता अपना आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात भी बिहार कृषि विश्वविद्यालय में कार्यरत रही, जिसमें उसने 18.06.2015 पर प्रत्यर्थी विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर (आनुवंशिकी और पादप प्रजनन) के रूप में प्रस्तुतीकरण की मांग की थी।

85. याचिकाकर्ता द्वारा वर्तमान रिट याचिका में लिया गया रुख, कि उसने कॉलम नं। 14 के रूप में "लागू नहीं", दिनांकित 10.02.2017 और 30.01.2017 की कार्यवाही के अपने जवाब में उन्होंने जो कहा था, उससे भिन्न है।अपने दिनांकित 17.02.2017 पत्र में, याचिकाकर्ता ने कहा था कि, शुरू में, उसने प्रतिवादी-विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के पद के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत किया था, दिनांकित 07.01.2012 विज्ञापन के अनुसार; उस समय वह कहीं भी कार्यरत नहीं थी; उसी आधार पर याचिकाकर्ता का पुराना बैंक ड्राफ्ट दिनांकित 06.03.2012 स्वीकार कर लिया गया था, साथ ही बाद के विज्ञापन ए-20/2015 के अनुसार किए गए उसके आवेदन के साथ; समय के दौरान, वह बिहार कृषि विश्वविद्यालय में चुनी गई थी; वह अपने पहले के आवेदन के आधार पर साक्षात्कार में उपस्थित हुई थी, और चुनी गई थी; 08.12.2015 पर सहायक प्रोफेसर के पद पर शामिल होने से पहले, उसने बिहार कृषि विश्वविद्यालय से 05.12.2015 पर इस्तीफा दे दिया था।

86. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, विज्ञापन सं। जून, 2015 में जारी विज्ञापन ए-20/ 2015 में सभी उम्मीदवारों को आवेदन किए गए पदों पर नियुक्ति के लिए अपनी उम्मीदवारी पर विचार करने के लिए एक नया आवेदन जमा करने की आवश्यकता थी।याचिकाकर्ता ने 18.06.2015 पर एक नया आवेदन जमा किया।इसलिए वह अपने दिनांकित 18.06.2015 आवेदन में सभी विवरणों को नए सिरे से भरने के लिए बाध्य थी।अवलम्ब ने अपने पहले के आवेदन पर यह तर्क देने के लिए रखा कि जब उन्होंने अपना पहले का आवेदन जमा किया था, तो उन्हें कहीं भी नौकरी नहीं दी गई थी, इसलिए इसका कोई फायदा नहीं है।

87. 2018 की रिट याचिका (एस/बी) संख्या 173/ 2018 में याचिकाकर्ता द्वारा लिया गया रुख, कि उसने कॉलम नं। 14 "लागू नहीं" के रूप में, क्योंकि वह 31.01.2015 पर बिहार कृषि विश्वविद्यालय में अपनी नियुक्ति के अनुसार 2 साल की अवधि के लिए परिवीक्षा पर थी, मान्य नहीं है।परिवीक्षा अवधि के दौरान भी याचिकाकर्ता बिहार कृषि विश्वविद्यालय में कार्यरत रहा।जबकि उन्होंने 07.12.2015 पर प्रतिवादी विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी नियुक्ति से ठीक दो दिन पहले 05.12.2015 पर बिहार कृषि विश्वविद्यालय में अपने द्वारा रखे गए पद से अपना इस्तीफा प्रस्तुत किया, ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि उनका इस्तीफा बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, इससे पहले कि वह 08.12.2015 पर प्रतिवादी-विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के रूप में कर्तव्यों में शामिल हुईं।बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा उनका इस्तीफा स्वीकार किए जाने के पश्चात ही याचिकाकर्ता को यह तर्क देते हुए सुना जा सकता मात्र कि वह अब बिहार कृषि विश्वविद्यालय में कार्यरत नहीं मात्र।इसलिए, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने अपने आवेदन पत्र दिनांक 18.06.2015 के कॉलम 14 को "लागू नहीं" के रूप में भरकर, न मात्र उसके कार्यरत होने के तथ्य को दबा दिया था, बल्कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम द्वारा उसके आवेदन को आगे बढ़ाने द्वारा बचने की भी मांग की थी।

88. यह तर्क, कि एक परिवीक्षाधीन होने के नाते याचिकाकर्ता को दो साल की परिवीक्षा की अवधि पूरी होने तक इस पद पर कोई कानूनी अधिकार नहीं था, मान्य नहीं है।याचिकाकर्ता अपनी परिवीक्षा के दौरान भी बिहार कृषि विश्वविद्यालय में कार्यरत रही। वास्तव में, जब उन्होंने प्रत्यर्थी-विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के लिए 18.06.2015 पर अपना आवेदन पत्र जमा किया, तो वह बिहार कृषि विश्वविद्यालय में कार्यरत थीं और इसके बाद 5 महीने से अधिक समय तक बिहार कृषि विश्वविद्यालय की सेवाओं में रहीं, जब तक कि उन्होंने 05.12.2017 पर अपना इस्तीफा जमा नहीं कर दिया।यह याचिकाकर्ता का मामला भी नहीं है कि उसने बिहार कृषि विश्वविद्यालय से अपना आवेदन प्रतिवादी-विश्वविद्यालय को भेजने का अनुरोध किया था, और बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने ऐसा करने अस्वीकार करना कर दिया था।कॉलम नं. निर्धारित आवेदन पत्र का 15, जिसे याचिकाकर्ता ने 18.06.2015 पर उसके द्वारा प्रस्तुत आवेदन में संदर्भित करने के लिए भी नहीं चुना था, याचिकाकर्ता को न मात्र बिहार कृषि विश्वविद्यालय से एक एन. ओ. सी. प्राप्त करने की आवश्यकता थी, बल्कि उसका आवेदन उक्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिवादी विश्वविद्यालय को अग्रेषित किया जाना

था।याचिकाकर्ता ने इस आवश्यकता का पालन करने से परहेज किया है, और बिहार कृषि विश्वविद्यालय या उक्त विश्वविद्यालय द्वारा उसके पक्ष में एन. ओ. सी. जारी किए बिना सीधे प्रतिवादी-विश्वविद्यालय को अपना आवेदन पत्र जमा कर दिया है।यह तर्क, कि इस तथ्य का खुलासा न करना भौतिक नहीं है, मान्य नहीं है।याचिकाकर्ता अपने आवेदन पत्र में सभी प्रासंगिक और भौतिक तथ्यों का खुलासा करने के लिए बाध्य थी।उन्होंने न मात्र बिहार कृषि विश्वविद्यालय में अपने रोजगार का विवरण देने से परहेज किया है, बल्कि वे बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा अपना आवेदन अग्रेषित करने और उक्त विश्वविद्यालय द्वारा उनके पक्ष में एनओसी जारी करने के लिए आवेदन पत्र में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने में भी विफल रही हैं।इन प्रासंगिक और भौतिक तथ्यों को छिपाना/दबाना/गलत तरीके से प्रस्तुत करना, निस्संदेह, याचिकाकर्ता की सेवाओं को समाप्त करने के लिए एक कानूनी आधार है।

X. विज्ञापन में घोषणा खंडः

89. श्री C.D बहुगुणा विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रस्तुत करेंगे कि सजा के विवादित आदेश में आवेदन पत्र के 'घोषणा खंड' से संदर्भ दिया विद्वान है, और उस आधार पर सजा के विवादित आदेश को उचित ठहराया विद्वान है; याचिकाकर्ता ने आवेदन पत्र के 'घोषणा खंड' को अतार्किक, तर्कहीन, असहनीय, मनमाना और अवैध के रूप में चुनौती दी है; याचिकाकर्ता द्वारा तथ्यों को छिपाया नहीं विद्वान है, ऊपर वर्णित परिस्थितियों को देखते हुए; आवेदन पत्र के 'घोषणा खंड' के आधार पर याचिकाकर्ता को सेवा से हटाने से कोई सेनूनी अधिनियम नहीं है; भले ही यह माना जाए कि आवेदन पत्र में याचिकाकर्ता की ओर से गलत घोषणा की गई थी, घोषणा खंड से अधिसेर नहीं है।

90. आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित आवेदन पत्र में निर्धारित घोषणा की आवश्यकता यह सुनिश्चित करने के लिए है कि आवेदन पत्र में सही और सही तथ्य बताए गए हैं और आवेदक तथ्यों को नहीं छिपाता है या अपनी पिछली सेवा और अभिलेख के बारे में जानकारी नहीं छुपाता है।याचिकाकर्ता ने बिहार कृषि विश्वविद्यालय के साथ अपनी पिछली सेवा के बारे में जानकारी को छुपाया और छिपाया है, और उसे दो सेमेस्टर के लिए अस्थायी बर्खास्तगी की सजा का सामना करना पड़ा है, जब वह प्रतिवादी-विश्वविद्यालय के साथ अपना Ph.D पाठ्यक्रम कर रही थी।घोषणा खंड, अपने आप में, प्रत्यर्थी-विश्वविद्यालय को याचिकाकर्ता की सेवाओं को समाप्त करने की शक्ति प्रदान करता है क्योंकि उसके द्वारा उसके आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियां स्पष्ट रूप से गलत और गलत हैं।यह तर्क कि तथ्यों को छिपाया नहीं गया था, मान्य नहीं है।

91. एक अस्पष्ट याचिका के अलावा कि घोषणा खंड अतार्किक, तर्कहीन, असहनीय, मनमाना और अवैध है, याचिकाकर्ता ने यह नहीं दिखाया है कि उक्त खंड को ऐसी किसी दुर्बलता से कैसे पीड़ित कहा जा सकता है।यह तर्क कि भले ही आवेदन पत्र में गलत घोषणा हो, विश्वविद्यालय और प्रबंधन बोर्ड दोनों अनुशासनात्मक कार्यवाही का सहारा लिए बिना याचिकाकर्ता की सेवाओं को समाप्त करने के हकदार नहीं हैं, मान्य नहीं है।जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, परिवीक्षाधीन की सेवाओं को समाप्त करने के लिए अनुशासनात्मक जांच आयोजित करने की आवश्यकता उन मामलों में लागू नहीं होती है जहां सेवा की समाप्ति रोजगार चाहने वाले व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में भौतिक तथ्यों को छिपाने/दबाने/गलत तरीके से प्रस्तुत करने के लिए होती है।

XI. 5वें प्रत्यर्थी द्वारा दायर W.P संख्या 153/ 2018:

92. श्री विनय कुमार, पाँचवें प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता, यह प्रस्तुत करेंगे कि, याचिकाकर्ता और पाँचवें प्रतिवादी की तुलनात्मक योग्यता के निष्पक्ष और उचित मूल्यांकन पर, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को ऐसे अंक दिए गए हैं जिनके लिए वह हकदार नहीं थी; यदि उन अंकों को कम कर दिया जाता है, तो यह पाँचवां प्रतिवादी है, न कि याचिकाकर्ता, जो योग्यता के क्रम में पहले स्थान पर होता; परिणामस्वरूप, पाँचवें प्रतिवादी को प्रतिवादी-विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर (आनुवंशिकी और पादप प्रजनन) के रूप में नियुक्त किया जाता; किसी भी स्थिति में, याचिकाकर्ता की सेवाओं पर प्रतिवादी-विश्वविद्यालय द्वारा समाप्त किया जा रहा है, इसलिए पाँचवें प्रतिवादी के कहने पर जिसकी शिकायत के आधार पर पूरी सच्चाई सामने आई।

93. श्री C.D। बहुगुणा, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रस्तुत करेंगे कि रिट याचिका सं। 2018 का 153 (एस/बी) 5वें प्रत्यर्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 04 <आई. डी. 1> के दंड का विवादित आदेश पारित होने के तुरंत पश्चात दायर किया गया था; इस याचिका में कई कृत्रिम आधार उठाए विद्वान थे जो कभी भी कुलाधिपति के समक्ष अभ्यावेदन के माध्यम द्वारा या अन्यथा नहीं उठाए विद्वान थे; उक्त रिट याचिका में केवल रोजगार प्राप्त करने के उद्देश्य द्वारा तुच्छ आधार उठाए विद्वान थे, जिद्वारा उन्होंने चयन प्रक्रिया के दौरान योग्यता के आधार पर खो दिया था; इस रिट याचिका में, चयन प्रक्रिया को पांचवें प्रत्यर्थी द्वारा चुनौती दी गई थी, जो विशेषज्ञ निकाय के निर्णय पर बैठे थे; और इस न्यायालय की खण्ड पीठ, जिसने पहले रिट याचिका नं. 2018 के 153 (एस/बी) का विचार था कि रिट याचिका सं। 2018 का 153 (एस/बी) याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका के निपटारे तक सुनवाई के लिए उत्तरदायी नहीं था, और यदि याचिकाकर्ता रिट याचिका में सफल हो जाता है, तो पांचवें प्रतिवादी द्वारा दायर रिट याचिका स्वचालित अभ्यावेदन द्वारा विफल हो जाएगी।

94. प्रतिवादी-विश्वविद्यालय की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजेंद्र डोभाल, **रघबीर चंद शर्मा 37** मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले पर अवलम्ब रखते हुए यह तर्क देंगे कि याचिकाकर्ता की सेवाओं की समाप्ति पर, प्रतिवादी-विश्वविद्यालय को अब नए सिरे से आवेदन बुलाने की आवश्यकता है; केवल यह तथ्य कि पांचवां प्रतिवादी क्रम संख्या पर खड़ा था। 2 योग्यता के क्रम में उसे सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति का दावा आदेश का कोई अधिकार प्रदान नहीं विद्वान जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता (उम्मीदवार जो पहले स्थान पर रहा) की सेवाओं को समाप्त कर दिया जाएगा और विश्वविद्यालय को योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करते हुए नए सिरे से एक विज्ञापन जारी करना होगा।

95. **रघबीर चंद शर्मा 37** मामले में, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि, जैसा कि अपीलकर्ता-राज्य के लिए सही तर्क दिया गया है, आवेदन आमंत्रित करने वाली अधिसूचना मात्र एक पद के संबंध में थी और चयन पैनल में पहले प्रतिवादी न मात्र पेश किया गया था, बल्कि प्रस्ताव की स्वीकृति पर, नियुक्त किया गया था; यह मात्र पश्चात में था कि वह इस्तीफा देने के लिए आया था; पहले उम्मीदवार की नियुक्ति के साथ, एकमात्र पद के लिए जिसके संबंध में विचार किया गया था और एक चयन पैनल तैयार किया गया था, पैनल से अस्तित्व समाप्त हो गया था, और इसकी उपयोगिता समाप्त हो गई थी और किसी भी तरह से, पैनल में कोई और वैध रूप से यह तर्क नहीं दे सकता था कि पैनल से नियुक्त व्यक्ति के पश्चात के इस्तीफे के सेरण उत्पन्न होने वाली रिक्ति में या किसी अन्य पद के लिए उन्हें नियुक्ति की पेशकश की जानी चाहिए थी।

96. **रघबीर चंद शर्मा 37** में, चयन सूची में पहला उम्मीदवार सेवा में शामिल हुआ था और बाद में इस्तीफा दे दिया था; और जो व्यक्ति रैंक में दूसरे स्थान पर था, उसने उस व्यक्ति के इस्तीफे के कारण हुई रिक्ति में नियुक्ति का दावा किया जिसने पहली रैंक हासिल की थी।इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि पैनल में कोई भी व्यक्ति वैध रूप से यह तर्क नहीं दे सकता था कि उसे उस रिक्ति में नियुक्ति की पेशकश की जानी चाहिए थी जो पहले नियुक्त किए गए व्यक्ति के पद से इस्तीफा देने के कारण हुई थी।वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता की सेवाओं को भौतिक तथ्यों को छिपाने/दबाने/गलत तरीके से प्रस्तुत करने के लिए समाप्त कर दिया गया था।

97. यद्यपि हम निर्णय में बैठने का कोई कारण नहीं देखते हैं, चयन समिति द्वारा किए गए मूल्यांकन के अभ्यास पर, याचिकाकर्ता को पांचवें प्रतिवादी की तुलना में अधिक अंक देने में, तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता की सेवाओं को प्रतिवादी-विश्वविद्यालय के साथ रोजगार की मांग करने वाले उसके आवेदन पत्र में सामग्री और प्रासंगिक तथ्यों को छिपाने/दबाने के लिए समाप्त कर दिया गया था।यद्यपि पाँचवाँ प्रतिवादी, अधिकार के अनुसार, याचिकाकर्ता की सेवाओं की समाप्ति के परिणामस्वरूप हुई रिक्ति में नियुक्ति का दावा नहीं कर सकता है, क्योंकि याचिकाकर्ता को शुरू में उक्त पद पर नियुक्त किए हुए 3 साल से अधिक समय बीत चुका है, हम संतुष्ट हैं कि ये सभी मामले न्यायालय के लिए नहीं हैं, बल्कि विश्वविद्यालय के प्रबंधन बोर्ड के लिए हैं, जिनकी जांच की जानी चाहिए, क्योंकि यह बोर्ड है जो नियुक्ति प्राधिकरण है और इस संबंध में निर्णय मात्र उनके द्वारा कानून के अनुसार लिया जा सकता है।

98.	इसलिए, यह पर्याप्त है कि प्रतिवादी-विश्वविद्यालय के प्रबंधन बोर्ड को अपने सदस्यों की एक बैठक जल्द से जल्द बुलाने का निर्देश दिया जाए, और किसी भी स्थिति में, इस आदेश की प्रमाणित प्रति की प्राप्ति की तिथि से तीन महीने के बाद नहीं, और एक विचारशील निर्णय लिया जाए कि क्या पांचवें प्रतिवादी को याचिकाकर्ता की सेवाओं की समाप्ति के परिणामस्वरूप हुई रिक्ति में सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए या नहीं या क्या विश्वविद्यालय को इसके बजाय, उक्त पद पर नियुक्ति के लिए योग्य उम्मीदवारों से नए आवेदन आमंत्रित करने चाहिए।

**XII.	<u>निष्कर्षः</u>**

99.	ऊपर की गई टिप्पणियों के आलोक में, याचिकाकर्ता द्वारा दायर 2018 की रिट याचिका (एस/बी)संख्या 173/ 2018 को खारिज कर दिया जाता है, और पाँचवें प्रतिवादी द्वारा दायर रिट याचिका (एस/बी) संख्या 153/ 2018 । का इन परिस्थितियों में, बिना किसी खर्चे के निपटारा कर दिया गया।

(रमेश रंगनाथन, C.J) 22.02.2019

(आलोक सिंह, जे.) 22.02.2019

राहुल